CMYK

RNI.No. — GUJHIN/2012/45192

सूरत भूमि

हिन्दी दैनिक

संपादक : संजय आर। मिश्रा

श्री 1008 महामंडलेश्वर
श्री स्वामी रामानंद दासजी महाराज
श्री रामानंद दास अन्नक्षेत्र सेवा ट्रस्ट, तपोवन आश्रम

स्व. पं. पू.1008 श्री रामानन्द जी
तपोवन मंदिर, मोरा गांव, सूरत

वर्ष-9 अंक: 331 ता. 13 जून 2021, रविवार कार्यालय:114, न्यु प्रियंका टाउनशीप अपार्टमेंट, डिंडोली, उधना सूरत (गुजरात) मो। 9327667842, 9825646069 पृष्ठ: 8 कीमत: 2:00 रुपये

ho@suratbhumi.com /Suratbhumi.com /Suratbhumi /Suratbhumi /Suratbhumi /Suratbhumi

सबके सामने आएगा भारत के युद्धों का इतिहास

युद्ध और सैन्य अभियानों से जुड़ी नई नीति को सरकार ने दी मंजूरी

नई दिल्ली।

भारत द्वारा अब तक लड़े गए कई युद्धों और सैन्य अभियानों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसको लेकर पहल की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध और अभियानों से जुड़े इतिहास को आर्काइव करने, उन्हें गोपनीयता सूची से हटाने और उनके संग्रह से जुड़ी नीति को शनिवार को मंजूरी दे दी।

रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, युद्ध इतिहास के समय पर प्रकाशन से लोगों को घटना का सही विवरण उपलब्ध होगा। शैक्षिक अनुसंधान के लिए प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध होगी और इससे अनावश्यक अफवाहों को दूर करने में मदद मिलेगी। इस नीति के दायरे में रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले सभी प्रतिष्ठान मसलन सेना की तीनों शाखाएं (थल-जल-वायु), इंटिग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, असम राइफल्स और भारतीय तटरक्षक आएंगे। वार डायरीज (युद्ध के दौरान घटित घटनाओं का विस्तृत ब्योरा), लेटर्स आफ प्रोसिडिंग्स (विभिन्न प्रतिष्ठानों के बीच अभियान/युद्ध संबंधी आपसी संवाद) और आपरेशनल रिकार्ड बुक (अभियान की पूरी जानकारी) सहित सभी सूचनाएं रक्षा मंत्रालय के इतिहास विभाग को मुहैया कराई जाएंगी। रक्षा मंत्रालय इन्हें सुरक्षित रखेगा, उनका संग्रह करेगा और इतिहास लिखेगा। रिकार्ड को सार्वजनिक करने की जिम्मेदारी पब्लिक रिकार्ड एक्ट 1993 और पब्लिक रिकार्ड रूल्स 1997 के तहत संबंधित संगठनों की होगी। नीति के अनुसार, सामान्य तौर पर रिकार्ड को 25 साल के बाद सार्वजनिक किया जाना चाहिए। रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि युद्ध/अभियान इतिहास के संग्रह के बाद 25 साल या उससे पुराने रिकार्ड की संग्रह विशेषज्ञों द्वारा जांच कराए जाने के बाद उसे राष्ट्रीय अभिलेखागार को सौंप दिया जाना चाहिए। बयान में कहा गया है कि युद्ध और अभियान के इतिहास के प्रकाशन के लिए विभिन्न विभागों से उसके संग्रह और मंजूरी की जिम्मेदारी इतिहास विभाग की होगी।

सैन्य इतिहासकारों को भी समिति में किया जाएगा शामिल

- रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया जाएगा।
- इसमें तीनों सेनाओं, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और अन्य प्रतिष्ठानों और जरूरत पड़ने पर प्रतिष्ठित सैन्य इतिहासकारों को शामिल किया जाएगा।
- समिति युद्ध और अभियान इतिहास का संग्रह करेगी। नीति के तहत युद्ध इतिहास के संग्रह और प्रकाशन के लिए स्पष्ट समय सीमा निर्धारित की जाएगी।
- युद्ध या अभियान पूरा होने के दो साल के भीतर समिति के गठन की बात कही गई है।

बिना लाइसेंस UP में नहीं बेच सकेंगे तंबाकू व सिगरेट, योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला

लखनऊ:

आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में अपराध व अपराधियों के खात्मे के साथ ही स्वस्थ प्रदेश की दिशा में भी अग्रसर हैं। इसी क्रम में योगी सरकार ने तंबाकू , सिगरेट आदि को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जिसके तहत राज्य में सिर्फ उन्हीं विक्रेताओं को तंबाकू, सिगरेट और संबद्ध उत्पाद बेचने की इजाजत होगी जो इसके लिए नगर निगम से लाइसेंस लेंगे। बता दें कि योगी सरकार के इस फैसले का वालंट्री हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने स्वागत किया है। वहीं इस आदेश से राज्य के लोगों को तंबाकू के नुकसान से बचाने में सहायता मिलेगी और इससे महत्वपूर्ण होगा कि बच्चों के लिए तंबाकू उत्पादों को देखना और खरीदने का मौका निकालना मुश्किल हो जाएगा। इस बाबत सीएम योगी ने कहा हम आशा करते हैं कि दूसरे राज्य यूपी द्वारा स्थापित मजबूत मिसाल का पालन करेंगे और लोगों, खासकर बच्चों की तंबाकू से रक्षा करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को एक एडवाइजरी लेटर भेजकर तंबाकू विक्रेताओं की लाइसेंसिंग नगर निगम से कराने की सिफारिश की है।

पहला कॉलम

कश्मीर के सोपोर शहर में आतंकवादी हमला, आतंकियों की अंधाधुंध फायरिंग में तीन जवान शहीद

श्रीनगर।

जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले के सोपोर में सुरक्षा बलों के साथ आर्तकियों की मुठभेड़ में तीन जवानों के शहीद होने की खबर हैं। नाके पर आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की जिसमें तीन जवानों शहीद हो गये और कई पुलिस वाले घायल हो गये हैं। शहीदों की संख्या बढ़ सकती हैं। सुरक्षा बलों और पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। आप-पास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। आतंकी हमला करने के इरादे से ही आये थे और उन्होंने लोगों को निशाना बनाकर गोलीबारी करनी शुरू कर दी। अभी तक आतंकियों के मारे जाने की खबर नहीं है। आर्तकियों को खोजने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया गया है।

डॉक्टरों पर हुए हमलों के खिलाफ आईएमए का 18 जून को देशव्यापी प्रदर्शन

नई दिल्ली। कोरोना काल में डॉक्टरों पर हुए हमलों के विरोध में भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) डॉक्टरों पर हमलों के खिलाफ 18 जून को देशव्यापी प्रदर्शन करेगा, जिसका नारा 'रक्षकों को बचाओ' होगा। संघ ने देशभर में अपनी सभी राज्य व स्थानीय शाखाओं से काली पट्टी, मास्क, रिबन, शर्ट (सभी काले रंग का) पहनकर प्रदर्शन करने और स्वास्थ्य कर्मियों को निशाना बनाकर की जाने वाली हिंसा के खिलाफ जागरुकता अभियान चलाने की अपील की है। आईएमए ने कहा कि इस मौके पर संवाददाता सम्मेलन भी आयोजित कर स्थानीय एनजीओ व स्वयंसेवी नेताओं से भी मुलाकात करने वाले है। संघ ने बीते दो हफ्तों में असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और अन्य स्थानों पर डॉक्टरों के खिलाफ हुई सिलसिलेवार हिंसा को 'बेहद चिंताजनक' करार दिया। इसने आईपीसी और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के साथ केंद्रीय अस्पताल एवं स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर संरक्षण अधिनियम को लागू करने, प्रत्येक अस्पताल में मानकीकरण और सुरक्षा बढ़ाने तथा अस्पतालों को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने की मांग की। संघ ने कहा, आईएमए की कार्य समिति ने सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद हमारी चिंता, रोष और एकजुटता व्यक्त करने के लिए, 18 जून 2021 को आईएमए राष्ट्रीय विरोध दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है, जिसमें 'रक्षकों को बचाओ' के नारे के साथ हमारे पेशे और पेशेवरों पर हमले को रोकने की मांग की जाएगी। संघ ने कहा कि 15 जून को राष्ट्रीय मांग दिवस मनाया जाएगा और देश भर में शाखाओं द्वारा संवाददाता सम्मेलन आयोजित किये जाएंगे। एलोपैथी को लेकर योग गुरु रामदेव की हालिया टिप्पणियों पर आईएमए ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया चल रही है और इसका पालन किया जाएगा।

राजस्थान में 10 आरएएस अधिकारियों का तबादला, सरकार ने पांच अफसरों को पदस्थापन की प्रतीक्षा में रखा

जयपुर। राजस्थान सरकार ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) के 10 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इनमें से पांच अफसरों को पदस्थापन की प्रतीक्षा (एपीओ) में रखा गया है। कार्मिक विभाग ने शुक्रवार देर रात यह आदेश जारी किया। इसके तहत आरएएस अधिकारी परशुराम धानका को भू प्रबंध अधिकारी टोंक, आनंदी लाल वैष्णव को जयपुर विकास प्राधिकरण मेंअतिरिक्त आयुक्त, राम खिलाड़ी मीणा को अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा व गोवर्धन लाल शर्मा को नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर में उपनिदेशक पद पर तैनात किया गया है। आदेश के तहत जहां छह आरएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है वहीं प्रतीक्षारत चार अधिकारियों को पदस्थापित किया गया है। वहीं, पांच आरएएस अधिकारियों को प्रतीक्षारत रखा गया है जिनमें हनुमान राम चौधरी, मुकेश कुमार मूंड, सुरेश कुमार यादव, लोकेश कुमार मीणा और रामनिवास जाट शामिल हैं।

ब्लैक फंगस की दवा पर नहीं लगेगा टैक्स

रेमडेसिवीर हुई सस्ती, वैक्सीन के मूल्यों में बदलाव नहीं

नई दिल्ली।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बताया कि मंत्रिसमूह की कोविड-19 से जुड़े उत्पादों पर दरों को घटाने की सिफारिशों को मान लिया गया है। नई दरें कम से कम 30 सितंबर तक प्रभावी रहेंगी। वित्त मंत्री ने प्रेस ब्रीफिंग मे बताया कि ब्लैक फंगस की दवा एम्फोरिसिटीन बी पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। साथ ही टोसिलीजुमेब पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि एंबुलेंस पर भी जीएसटी दर को घटाकर कर 12 फीसद कर दिया गया है। वेंटिलेटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, कोविड-19 टेस्टिंग किट, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और बीपैप मशीन पर जीएसटी को मौजूदा 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। हैंड सैनिटाइजर और तापमान जांचने वाले उपकरणों पर भी जीएसटी को घटाकर 5 फीसद कर दिया गया है। साथ ही पल्स ऑक्सीमीटर, एचएफएनसी डिवाइस पर भी जीएसटी को घटाकर 5 फीसद किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, आज की बैठक का एक ही एजेंडा था। बैठक में मंत्रियों के समूह, जिनका गठन पिछली जीएसटी काउंसिल की बैठक में हुआ था, के द्वारा कोविड-19 से जुड़े उत्पादों पर टैक्स में राहत को लेकर आई सिफारिशों पर विचार किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा, मंत्रिसमूह के चेयरमैन ने नियत तारीख से दो दिन पहले 6 जून को रिपोर्ट सबमिट की। आज की बैठक में वित्त मंत्रालय ने इन सिफारिशों पर चर्चा की है। वित्त मंत्री ने कहा, केवल 3 वस्तुओं पर दरों के बारे में विचार किया गया और जिस अवधि तक यह वैध रहेगा, उसमें भी थोड़ा बदलाव किया गया है।

कोरोना संकट के दौरान मनरेगा योजना को मजबूती दें सरकार: राहुल गांधी

नई दिल्ली ।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान लगे लॉकडाउन से पैदा हुई आर्थिक तंगी से निपटने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को मजबूती दी जानी चाहिए। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में मनरेगा से लोगों को मदद मिलने से जुड़ी खबरों का हवाला देकर कहा कि इस समय जनहित सबकी जिम्मेदारी है। कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया,देश के कमजोर वर्ग को अबकी बार भी मनरेगा से राहत मिल रही है। लॉकडाउन से पैदा हुई आर्थिक तंगी से निपटने के लिए योजना को और मजबूत करना जरूरी है। सरकार किसी की भी हो, जनता भारत की है और जनहित हमारी जिम्मेदारी है। कांग्रेस ने कुछ महीने पहले भी सरकार से आग्रह किया था कि मनरेगा का बजट बढ़ाया जाए, ताकि रोजगार छिन जाने के कारण शहरों से गांवों का रुख करने वाले ज्यादा से ज्यादा लोगों को जीविका का साधन मिल सके।

फोटो ले रहे पुलिसवालों पर प्रदर्शनकारी किसानों का हमला

-एफआईआर दर्ज; टिकैत बोले- हम हिंसा नहीं करते

नई दिल्ली।

सिंघु बॉर्डर के पास किसानों ने फोटो खींच रहे दो पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं, किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि किसान हिंसा में शामिल नहीं होते। एफआईआर के मुताबिक, 10 तारीख को एएसआई रमेश और चंद्र सिंह सिंघु बॉर्डर के पास खड़े होकर फोटो खींच रहे थे। तभी एक महिला प्रदर्शनकारी अपने 2-3 साथियों के साथ वहां आ गई और पुलिसकर्मियों से मारपीट की। इस मामले में नरेला थाने में अज्ञात प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में आरोप लगाया है कि महिला और उसके साथियों ने उन दोनों के साथ न सिर्फ बदसलूकी की, बल्कि गाली-गलोज और मारपीट भी की। वहीं, इस मामले पर राकेश टिकैत ने बयान में दावा किया कि किसान हिंसा में शामिल नहीं होते। हो सकता है कि वो (पुलिस) सिविल ड्रेस में हों और उन्हें लगा होगा कि ये मीडिया वाले हैं जो हमें गलत तरह से दिखाते हैं। टिकैत ने कहा, पुलिस और सरकार किसानों को भड़काना चाहते हैं। अगर वो (पुलिस) कई दिनों प्रदर्शन स्थल पर आ रहे थे तो उन्हें बात करनी चाहिए थी। वो एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, लेकिन उसमें लिखने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए।

भाजपा के खिलाफ 2024 के लिए विरोधी पार्टियों का महागठबंधन जरुरी: एनसीपी

मुंबई।

चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के प्रमुख शरद पवार के बीच मुलाकात के एक दिन बाद पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ रुख रखने वाली पार्टियों के महागठबंधन की जरूरत है। किशोर और पवार के बीच करीब तीन घंटे चली बैठक के बाद राजनीतिक हलके में अटकलों का बाजार गरम है। हालांकि, बैठक में क्या बात हुई, इस बारे में पता नहीं चला है। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने कहा, अगले आम चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ रुख रखने वाली पार्टियों के महागठबंधन की जरुरत है। एनसीपी अध्यक्ष पवार ने भी बीजेपी का मुकाबला करने के लिए सभी दलों के राष्ट्रीय गठबंधन की बात कही है। उन्होंने कहा है कि वह इसतरह के दलों को साथ लाने का प्रयास करने वाले हैं। उन्होंने कहा,चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को आंकड़ों और सूचनाओं की पूरी जानकारी है... तीन घंटे चली चर्चा में यह मुद्दा भी पक्का आया होगा। गौरतलब है कि पिछले महीने शिवसेना नेता संजय राउत ने राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों के गठबंधन की जरुरत पर बल देकर कहा था उन्होंने इस मुद्दे पर शरद पवार से बात की है। इससे पहले उन्होंने यह भी कहा था कि यूपीए के फिर से निर्माण की आवश्यकता है ताकि वह बीजेपी के मजबूत विकल्प के रूप में उभर सके और नये मोर्चे का नेतृत्व पवार जैसे वरिष्ठ नेताओं को करना चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस-2021 के लिए पूर्वावलोकन कार्यक्रम आयोजित, नमस्ते योग ऐप लॉन्च

नई दिल्ली ।

7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूर्वावलोकन कार्यक्रम शुक्रवार की देर शाम ऑनलाइन तरीके से आयोजित किया, जिसमें दो केंद्रीय मंत्रियों के साथ कई विख्यात योग गुरु तथा अनुभवी योग व्याख्याता वर्चुअल प्लेटफार्म पर विश्व समुदाय से यह अपील करने के लिए एकजुट हुए कि लोग खुद अपनी तथा मानवता की बेहतरी के लिए अपने दैनिक जीवन में योग को अपनाएं। कार्यक्रम के दौरान, योग को समर्पित एक मोबाइल ऐप्लीकेशन 'नमस्ते योग' भी लॉन्च किया गया। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई) के सहयोग से आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित एक घंटे चलने वाले इस कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर तथा केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) किरेन रिजिजू ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस-2021 की केंद्रीय थीम 'योग के साथ रहें, घर पर रहें'के महत्व को रेखांकित किया, जबकि श्री श्री रविशंकर, सद्गुरु जग्गी वासुदेव, बहन शिवानी और स्वामी चिदानंद सरस्वती जैसे अंतरराष्ट्रीय ख्याति और अनुयायियों वाले अध्यात्मिक नेताओं और योग गुरुओं ने गहरे अध्यात्मिक आयामों से लेकर इसके दैनिक जीवन तथा कोविड संबंधित उपयोगिता तक, योग के विभिन्न अनूठी और व्यापक विशेषताओं पर बल दिया। कई अन्य प्रख्यात हस्तियों ने भी अपने गहन संदेशों के साथ समारोह की शोभा बढ़ाई। प्रकाश जावडेकरने कहा कि योग एक स्वस्थ और सुखी जीवन का मार्ग है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में सरकार समाज के सभी वर्गों के बीच योग को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्नशील है। आयुष मंत्री किरेन रिजिजू ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस-2021 पर दूरदर्शन पर 10 दिनों की श्रृंखला के बारे में जानकारी दी और कहा कि इस श्रृंखला का मूल संदेश है, 'योग के साथ रहें, घर पर रहें'जो स्वास्थ्य आपातकाल के वर्तमान समय में प्रासंगिक है। स्वास्थ्य को बढ़ावा देने तथा रोगों के प्रबंधन तथा रोकथाम में योग की उपयोगिता अच्छी तरह स्थापित हो चुकी है। प्रतिरक्षण निर्माण तथा तनाव से राहत की दिशा में योग के लाभ साक्ष्यों से प्रदर्शित हो चुके हैं। मंत्री ने कहा कि, 'मंत्रालय का उद्देश्य पिछले वर्षों की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यकलापों के दायरे में और अधिक नागरिकों को लाना तथा इसके जरिये हमारे समाज के सभी वर्गों को योग के माध्यम से होने वाले शारीरिक और भावनात्मक कल्याण को फैलाना है। मंत्री ने औपचारिक रूप से योग को समर्पित एक मोबाइल ऐप्लीकेशन 'नमस्ते योग'लॉन्च करते हुए कहा कि इसका डिजाइन आम जनता के लिए एक सूचना प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया गया है। इसका उद्देश्य योग के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना तथा व्यापक समुदाय के लिए इसे पहुंच योग्य बनाना है।

सचिन पायलट से मुलाकात कर सकती हैं प्रियंका

जितिन एपिसोड के बाद कांग्रेस एक्टिव

नई दिल्ली।

कांग्रेस से लगातार दिग्गज नेता अन्य दलों में शामिल होते जा रहे हैं। अब माले की नजाकर को समझ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी खुद इस सीएम अशोक गहलोत तथा सचेन पायलट के विवाद को खत्म करने के लिए सामने आई हैं। इसी रणनीती के तहत वे सचिन पायलट से रविवार को मुलाकात कर सकती हैं। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद के रूप में दो बड़े झटके सह चुकी कांग्रेस अब सतर्क हो गई है और कोई खतरा मोल नहीं लेना चाह रही है। माना जा रहा है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस आलाकमान और सचिन पायलट के बीच में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पुल की भूमिका निभा रहे हैं। जानकारी के अनुसार, बीते दो दिनों से कमलनाथ सचिन पायलट के संपर्क में बने हुए हैं और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से भी बातचीत कर रहे हैं। राजस्थान में गहलोत व पायलट के बीच में कई बार नाराजगी खुलकर सामने आ चुकी है। पायलट गुट के कई विधायक भी खुलकर नाराजगी जता चुके हैं। हालांकि, पिछली बार प्रियंका गांधी वाड्रा के कहने पर पायलट ने तेवर कम कर लिए थे। इस बीच, कांग्रेस आलाकमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। राहुल गांधी के दफ्तर से लगातार बातचीत का दौर जारी है। उधर, राजस्थान के प्रभारी अजय माकन भी सचिन पायलट के मुद्दे पर राहुल गांधी के दफ्तर से संपर्क में हैं, लेकिन पायलट अब माकन के जरिए नहीं, बल्कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के जरिए पूरे मामले को सुलझाना चाहते हैं। अजय माकन ने कहा है कि जल्दी ही राजस्थान सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार होगा और राजनीतिक नियुक्तियां की जाएंगी। वह सचिन पायलट से भी लगातार बातचीत कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अशोक गहलोत भी सारे मुद्दों को जल्द ही सुलझाने के पक्ष में हैं। उधर, राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान के प्रभारी अजय माकन से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। दोनों के बीच में शाम को बैठक होगी। मीडिया से बातचीत में गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सचिन पायलट हमारे पार्टी के नेता है। उन्होंने तमाम तरह के कयासों के बीच कहा कि जब बीजेपी खुद ही टूट रही है, तब पायलट वहां क्यों जाएंगे। उन्होंने पूरे विवाद को घर का मसला करार देते हुए कहा कि हम इसे बैठकर सुलझा लेंगे।

पंजाब के विकास का अहम पड़ाव साबित होगा बसपा-शिअद गठबंधन : मायावती

नई दिल्ली ।

पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन को ऐतिहासिक कदम बताते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने लोगों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। एक के बाद एक तीन ट्वीट में मायावती ने कहा कि पंजाब में आज शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी द्वारा घोषित गठबंधन एक नई राजनीतिक व सामाजिक पहल है, जो राज्य की जनता के बहुप्रतीक्षित विकास, प्रगति व खुशहाली के लिए नए युग की शुरुआत करेगी। अपने ट्वीट में मायावती ने लिखा कि वैसे तो पंजाब में समाज का हर तबका कांग्रेस पार्टी के शासन में व्याप्त गरीबी, भ्रष्टाचार व बेरोजगारी आदि से जूझ रहा है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा मार दलितों, किसानों, युवाओं व महिलाओं आदि पर पड़ रही है, जिससे मुक्ति पाने के लिए इस गठबंधन को कामयाब बनाना होगा। उन्होंने पंजाब की समस्त जनता से अपील की कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में इस गठबंधन को समर्थन दें। गठबंधन की सरकार बनने के बाद ही लोगों के जीवन में गुणात्मक बदलाव आएगा। पंजाब में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शिरोमणि अकाली दल (शिअद) और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने शनिवार को गठबंधन कर लिया है।

गठबंधन की घोषणा करते हुए शिअद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने इसे पंजाब की राजनीति में नया सवेरा बताया। बसपा महासचिव सतीश चन्द्र मिश्रा की उपस्थिति में उन्होंने कहा आज ऐतिहासिक दिन है। यह पंजाब की राजनीति की बड़ी घटना है।

उन्होंने कहा कि शिअद और बसपा साथ मिलकर 2022 विधानसभा चुनाव और अन्य चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मायावती नीत बसपा पंजाब के 117 विधानसभा सीटों में से 20 पर चुनाव लड़ेगी, बाकी सीटें शिअद के हिस्से में आएंगी। बसपा के हिस्से में जालंधर का करतारपुर साहिब, जालंधर पश्चिम, जालंधर उत्तर, फगवाड़ा, होशियारपुर सदर, दासुया, रुपनगर जिले में चमकौर साहिब, पठानकोट जिले में बस्सी पठाना, सुजानपुर, अमृतसर उत्तर और अमृतसर मध्य आदि सीटें आई हैं। इससे पहले शिअद का भाजपा के साथ गठबंधन था, लेकिन पिछले साल केन्द्र द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों के विरोध में शिअद ने एनडीए से नाता तोड़ लिया था। पहले शिअद के साथ गठबंधन में भाजपा 23 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ती थी।

झारखंड में कोरोना से 5 लोगों की मौत, 293 नए केस आए सामने

रांची। झारखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से पांच और लोगों की मौत हो गयी जबकि संक्रमण के 293 नये मामले सामने आये। स्वास्थ्य विभाग की आज जारी रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5081 तक पहुंच गयी। जबकि राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 342774 हो गयी है। राज्य में 4514 अन्य संक्रमितों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में जारी है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने 22 अप्रैल से झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की थी। 22 अप्रैल को राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 40942 थी। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की बंदिशों के कारण अब यह आंकड़ा तेजी से घट रहा है। 11 जून को राज्यभर में कोरोना का आंकड़ा 4220 पर पहुंच गया है, जबकि संक्रमण से सिर्फ 1 व्यक्ति की मौत हुई है। मरीज मिलने की संख्या मात्र 291 रही। कोरोना को लेकर सबसे ज्यादा चिंता का विषय हर दिन नए पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या थी। 22 अप्रैल की ही बात करें तो उस दिन कुल नए पॉजिटिव मरीजों की संख्या राज्य भर में 7 हजार 595 तक पहुंच गई थी। अगले कुछ दिनों बाद राज्य में एक्टिव केस का आंकड़ा 60000 के आस-पास था। लेकिन स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के 51 दिन बाद यानी 11 जून के आंकड़ों पर गौर करें तो इसका असर साफ दिखता है। 11 जून को राज्य में कुल एक्टिव केस की संख्या घट कर 4220 पर पहुंच गई है।

संक्षिप्त समाचार

अमेठी जिला चिकित्सालय में स्थापित आक्सीजन संयंत्र का स्मृति ईरानी ने किया उद्घाटन

अमेठी। केंद्रीय वस्त्र और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने शनिवार को संयुक्त जिला चिकित्सालय में आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा स्थापित ऑक्सीजन संयंत्र का उद्घाटन किया। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के दौरान यह तीसरी बार है जब स्मृति ईरानी अमेठी के औचक दौरे पर आई हैं। उनका यहां आने का पहले से कार्यक्रम तय नहीं था। पिछले माह उन्होंने जिले के लिए तीन टन ऑक्सीजन भिजवाया था और उसी के साथ यहां छह ऑक्सीजन संयंत्र लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसमें आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा लगाए गए ऑक्सीजन संयंत्र की शनिवार से शुरूआत हो गई है। इस संयंत्र में प्रतिदिन 100 सिलेंडर भरे जा सकेंगे। इसके निर्माण में करीब 75 लाख रुपए की लागत आई है। ईरानी ने जिलाधिकारी अरूण कुमार, पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह, मुख्य विकास अधिकारी अंकुर लाठर एवं मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ आशुतोष दुबे से महामारी से निपटने के प्रबंध के बारे में जानकारी ली।

3-डी भूकंपीय आंकड़े समुद्र तल और तलछटों के टकराव से उत्पन्न होने वाले समुद्री खतरों की पहचान करने में मदद करेंगे

नई दिल्ली । समुद्र की बेहद गहराई में तलछट उसके तल के ऊपर मौजूद रहते हैं और इन तलछटो में गतिशीलता भी बनी रहती है, ऐसे में समुद्र में उठने वाले कई तरह के खतरे की संभावना बनती है। उत्तरी न्यूजीलैंड के अपतटीय इलाके तारानाकी बेसिन में समुद्री तलछट की निचली सतह और समुद्र तल के बीच होने वाली परस्पर क्रिया को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने अब 3-डी भूकंपीय आंकड़ों का उपयोग किया है। यह आंकड़े समुद्र से उत्पन्न होने वाले खतरों की पहले से पहचान करने में मदद कर सकते हैं। समुद्र से खतरा तब उत्पन्न होता है जब समुद्र तल अस्थिर होता है और गहरे समुद्र के तल से समुद्री तलछट जमीन की ओर गतिशील हो जाते हैं। इस गतविधि की पहचान नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में, समुद्र तल की अस्थिरता के कारण ड्रिलिंग रिंग की मौजूदगी स्थिति को और खतरनाक बना देती है। समुद्र तल पर प्रवाह के दौरान तलछट की गतिशीलता को समझन और भूस्खलन जैसे समुद्री खतरों का पता लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में आकार के आधार पर हो रहे इस बदलाव की जांच एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है और इसके लिए भूभौतिकीय / भूकंपीय पूर्वेक्षण विधियां आवश्यक हैं।

फारूक अब्दुल्ला ने जताया दिग्विजय का आभार, कहा- उन्होंने लोगों की भावनाओं को समझा

नई दिल्ली। दिग्विजय सिंह के एक बार फिर से कश्मीर में आर्टिकल 370 के लागू करने वाले बयान के बाद देश में सियासी सरगर्मी पैदा हो गई है। दिग्विजय सिंह के इस बयान पर भाजपा ने उन पर हमला बोला है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने लोगों की भावनाएं समझीं, इसके लिए उन्हें धन्यवाद। फारूक अब्दुल्ला ने कहा मैं दिग्विजय सिंह का बहुत आभारी हूं। उन्होंने लोगों की भावनाओं को महसूस किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस पर दोबारा गौर करेगी। ज्ञात हो कि दिग्विजय सिंह ने क्लब हाउस के ऑडियो में दिग्विजय सिंह आर्टिकल 370 को फिर से लागू करने की बात कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो वह 370 हटाने के फैसले पर विचार करेगी। खास बात यह है कि दिग्विजय के क्लब हाउस चैट में पाकिस्तानी रिपोर्टर शाहज़ेब भी मौजूद थे। हालांकि, ऑडियो की अब तक पुष्टि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि ऑडियो 12 मई का है। जब उन्होंने पाकिस्तानी रिपोर्टर के सामने धारा 370 को हटाने को लेकर बड़ी बात कही थी।

कोविन एप को हैंक करने की खबर को सरकार ने निराधार बताया

नई दिल्ली। देश में कोरोना वैक्सीनेशन में किसी प्रकार की कोई धोखाधड़ी न हो इसके लिए मोदी सरकार ने कोविन एप बनाया था। कोविन एप के जरिए ही आप वैक्सीन बुक कर सकते हैं। इस तरह सरकार को वैक्सीन का पूरा डेटा जानकारी मिलती रहती है। एक दिन पहले ही कोविन एप के हैक होने की खबर आई। हालांकि सरकार ने इस खबर को निराधार बताया है। सरकार ने कोविन पोर्टल को हैक करने और आंकड़े लीक होने के दावों को खारिज करते हुए उन्हें 'निराधार' बताया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की कम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम को-विन प्रणाली को कथित तौर पर हैक करने के मामले की जांच कर रही है। टीका प्रशासन पर अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष डॉ. आर एस शर्मा ने स्पष्ट किया, 'को-विन प्रणाली को कथित तौर पर हैक करने और आंकड़े लीक होने से संबंधित डार्क वेब पर तथाकथित हैकरों के दावे निराधार हैं। हम यह सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर आवश्यक कदम उठाते रहने वाले हैं, कि को-विन पर लोगों के आंकड़े सुरक्षित रहें।' को-विन पोर्टल कोविड-19 टीकाकरण अभियान का अहम हिस्सा है।

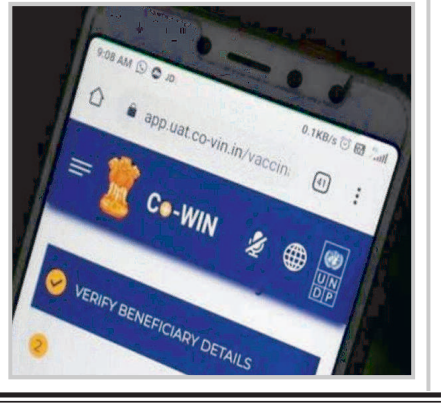

युद्ध से जुड़े इतिहास संग्रह और उसे सार्वजनिक करने की नीति को राजनाथ ने दी मंजूरी

नई दिल्ली ।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय द्वारा युद्ध और अभियानों से जुड़े इतिहास को आर्काइव करने, उन्हें गोपनीयता सूची से हटाने और उनके संग्रह से जुड़ी नीति को शनिवार को मंजूरी दे दी। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा युद्ध इतिहास के समय पर प्रकाशन से लोगों को घटना का सही विवरण उपलब्ध होगा, शैक्षिक अनुसंधान के लिए प्रमाणिक सामग्री उपलब्ध होगी और इससे अनावश्यक अफवाहों को दूर करने में भी मदद मिलेगी। इस नीति के अनुसार, रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले सभी प्रतिष्ठान मसलन सेना की तीनों शाखाएं (थल-जल-वायु), इंटिग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, असम राइफल्स और भारतीय तटरक्षक वार डायरीज (युद्ध के दौरान घटित घटनाओं का विस्तृत ब्योरा), लेटर्स ऑफ प्रोसिडिंग्स (विभिन्न प्रतिष्ठानों के बीच अभियान/युद्ध संबंधी आपसी संवाद) और ऑपरेशनल रिकॉर्ड बुक (अभियान की पूरी जानकारी) सहित सभी सूचनाएं रक्षा मंत्रालय के इतिहास विभाग को मुहैया कराएंगे जो इन्हें सुरक्षित रखेगा, उनका संग्रह करेगा और इतिहास लिखेगा। रक्षा मंत्रालय के अनुसार पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 1993 और पब्लिक रिकॉर्ड रूल्स 1997 के अनुसार रिकॉर्ड को सार्वजनिक करने की जिम्मेदारी संबंधित प्रतिष्ठान की है। नीति के अनुसार, सामान्य तौर पर रिकॉर्ड को 25 साल के बाद सार्वजनिक किया जाना चाहिए। बयान के अनुसार, युद्ध/अभियान इतिहास के संग्रह के बाद 25 साल या उससे पुराने रिकॉर्ड की संग्रह विशेषज्ञों द्वारा जांच कराए जाने के बाद उसे राष्ट्रीय अभिलेखागार को सौंप दिया जाना चाहिए। बयान में कहा गया है कि युद्ध और अभियान के इतिहास के प्रकाशन के लिए विभिन्न विभागों से उसके संग्रह और मंजूरी के लिए इतिहास विभाग जिम्मेदार होगा।

पंजाब में हुआ बड़ा राजनीति गठजोड़, शिअद और बसपा ने 25 साल बाद मिलाया हाथ

-बसपा नेता और सांसद सतीश मिश्रा ने कहा- पंजाब की सियासत में यह ऐतिहासिक दिन

चंडीगढ़ ।

अगले साल होनेवाले विधानसभा चुनाव के पूर्व शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी ते बीच आज गठबंधन हो गया। शिअद प्रधान सुखबीर सिंह बादल और बसपा नेता सतीश मिश्रा ने यहां इसका एलान किया। तीन कृषि कानूनों पर भाज से गठबंधन टूटने के बाद शिअद व बसपा से 25 साल बाद साथ आए हैं। इस मौके पर बसपा नेता और सांसद सतीश मिश्रा ने कहा कि पंजाब की सियासत में यह ऐतिहासिक दिन है, जब बसपा और शिअद का गठबंधन हुआ है। अब पंजाब की यह सबसे बड़ी सियासी ताकत हो गई है। 1986 में दोनों पे र्टियों ने साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा था तो राज्य की 13 सीटों में से 11 पर जीत दर्ज की थी। गौरतलब है कि पहले बसपा के हिस्से में भी 23 ही सीटें गठबंधन में थीं।बाद में दोनों दलों में सीटों के बारे में समझौता हो गया और बसपा के हिस्से से में 20 व शिअद के हिस्से से में 97 सीटें आई हैं। इससे पहले 1996 के लोकसभा चुनाव में शिअद ने बसपा के साथ गठजोड़ किया था जिसमें बसपा को तीन सीटों होशियारपुर, फिल्लौर और फिरोजपुर में सफलता मिली थी, लेकिन 1997 के विधानसभा चुनाव तक आते आते यह गठबंधन टूट गया है और अकाली दल ने भाजपा के साथ नया गठजोड़ बना लिया। अब जबकि पंजाब में विधानसभा चुनाव को मात्र आठ महीने बचे हैं। ऐसे में नए बन रहे समीकरणों के चलते इस बार चुनाव काफी दिलचस्प होगा और दलित राजनीति के इर्द गिर्द ही घूमेगा। इससे पहले भाजपा ने भी पंजाब में दलित चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर लाने का एलान किया हुआ है। इससे पहले कि पार्टी किसी को दलित चेहरे के रूप में आगे करती, उसके अपने पुराने गठजोड़ के साथी शिअद ने 2022 के चुनाव में दलित को उपमुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर दी। उधर, आम आदमी पार्टी ने भी 2018 में दलित वोट को कैश करने के लिए सुखपाल सिंह खैहरा को हटाकर हरपाल चीमा के रूप में एक दलित नेता को आगे किया और उन्हें विपक्ष का नेता बनाया। कांग्रेस भी पिछले कई दिनों से दलित वोट बैंक को भुनाने का प्रयास कर रही है। बसपा को 2017 में मात्र 1।50 फीसद वोट शेयर मिला जो 2019 के संसदीय चुनाव में 3।52 फीसद हो गया। यह पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि थी जिस पर सोचने के लिए दूसरी पार्टियां भी मजबूर हुईं। दोआबा की कई विधानसभा सीटों पर बसपा के उम्मीदवारों ने उम्मीद से कहीं अधिक अच्छा प्रदर्शन किया।

भाजपा से टीएमसी में घर वापसी करने वाले मुकुल रॉय ने केंद्र से मिली सुरक्षा हटाने को कहा

काम न आई प्रधानमंत्री की युक्ति, मुकुल राय पर चल गया सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक का जादू

कोलकाता।

भजपा तथ केंद्र की तमाम कोशिशों के बाद भी तृणमूल कांग्रेस में लौट आए मुकुल रॉय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिख उन्हें दी गई केंद्रीय सुरक्षा वापस लेने को कहा है। एक दिन पहले ही मुकुल रॉय अपने पुत्र शुभ्रांशु के साथ तृणमूल कांग्रेस में वापस लौट आए हैं। सीएम ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल सांसद अभिषेक के हाल ही में शहर के एक अस्पताल में रॉय की पत्नी से मिलने के बाद उनकी घर वापसी को लेकर अटकलें तेज हो गई थीं। इसके बाद, रॉय को भाजपा में बनाए रखने के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर रॉय की पत्नी के स्वास्थ्य की जानकारी ली थी। हालांकि, उस समय रॉय ने भाजपा छोड़ने की बात से इनकार किया था, लेकिन उन्होंने चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस समर्थकों की कथित हिंसा पर चर्चा के लिए भाजपा की राज्य इकाई की बैठक में भाग नहीं लिया था। कभी तृणमूल में दूसरे सबसे प्रमुख नेता रहे रॉय को नारद स्टिंग मामले में नाम आने के बाद फरवरी, 2015 में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से हटा दिया गया था। वह नवंबर, 2017 में भाजपा में शामिल हुए थे। जाने-माने राजनीतिक विश्लेषक और कलकत्ता रिसर्च ग्रुप के सदस्य रजत रॉय ने कहा कि तृणमूल चुनिंदा लोगों को वापस लेगी। उन्होंने कहा कि इसका मकसद भाजपा को संगठनात्मक रूप से कमजोर करना होगा, लेकिन साथ ही पार्टी बहुत सारे दलबदलुओं को वापस नहीं लेना चाहेगी क्योंकि इसे असंतोष को पुरस्कृत किए जाने के तौर पर देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि मुकुल रॉय का मामला विशेष है क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है कि वह संगठन के लिहाज से अहम हैं।

यूपी-उत्तराखंड में तेज हवा के साथ बारिश,

बदरीनाथ हाई-वे पर भूस्खलन

नई दिल्ली ।

बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल एवं ओडिशा के तट पर कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान इसके और सशक्त होने की संभावना है। पंजाब और दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऊपर भी चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इसकी वजह से मौसमी गतिविधियों में तेजी से बदलाव हो रहा है। मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार, उत्तर प्रदेश के अधिकतर इलाकों में शनिवार को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी हल्की बारिश होने की उम्मीद है। जिससे उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर प्रदेश के कासगंज, देवबंद, नजीबाबाद, सहारनपुर, चांदपुर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, चंदौसी, बिलारी और आस-पास के इलाकों में आज (शनिवार) मौसम का मिजाज बदला और बारिश होने से गर्मी से राहत मिली है। उत्तराखंड में भारी बारिश से कई जगह भूस्खलन हुआ है। बद्रीनाथ हाईवे के किनारे बसे नरकोटा गांव में कई घरों में मलबा घुसने से अफरा तफरी का माहौल है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले चार दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी करते हुए स्थानीय प्रशासन को पर्याप्त सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले चार दिन भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने के साथ तेज हवाओं की चलने की आशंका है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, नैनीताल और चंपावत में कहीं-कहीं भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गर्मी से कुछ राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग ने शनिवार को आसमान में बादल छाए रहने और झोंके वाली हवा के साथ हल्की या मध्यम बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। मौसम विभाग ने 15 जून तक दिल्ली में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। आईएमडी ने मुंबई और ठाणे समेत कई स्थानों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। आईएमडी के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और रत्नागिरि जिलों में 13-14 जून को अत्यंत भारी बारिश हो सकती है। रायगढ़ और रत्नागिरि जिलों में शनिवार के लिए भी इसी तरह का अलर्ट जारी है। राजस्थान में गर्मी का प्रकोप जारी है। प्रदेश में गंगानगर में अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को चूरू में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस, करौली में 43.6 डिग्री, चित्तौड़गढ़-पिलानी में 43.3-43.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, राज्य के अन्य जिलों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया।

विभाग ने शनिवार को पश्चिमी राजस्थान के हनुमानगढ़, गंगानगर जिलों में लू चलने और पूर्वी राजस्थान के जिलों में तेज हवाओं के साथ कहीं-कहीं बूंदाबादी की संभावना जताई है।

सार समाचार

चीन में रसायन कंपनी में जहरीली गैस रिसाव से आठ लोगों की मौत, तीन बीमार

बीजिंग। दक्षिणी चीन के गुइझोऊ प्रांत में शनिवार को एक रसायन कंपनी में जहरीली गैस के रिसाव की चपेट में आने से कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य बीमार पड़ गए। मीडिया में आई खबर से यह जानकारी मिली है। स्थानीय अधिकारियों ने सरकारी शिन्हुआ समाचार एजेंसी को बताया कि प्रांतीय राजधानी गुईयांग में पुलिस को तड़के यह जानकारी मिली कि कुछ लोग रसायन कपनी के निकट बेहोश पड़े हुए हैं। प्राथमिक जांच के आधार पर अधिकारियों ने बताया कि एक वाहन से कंपनी के श्रमिक रसायन उतार रहे थे, तभी मिथाइल फॉर्मेट का रिसाव हुआ। वाहन पर हुबेई प्रांत का लाइसेंस प्लेट लगा हुआ था। आठ लोगों की मौत की पुष्टि हुई है जबकि तीन व्यक्ति अस्पताल में भर्ती हैं। आगे की जांच जारी है।

अफगानिस्तान में हजारा समुदाय के लोगों पर हमले की यूएनएससी और भारत ने की निंदा

संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) ने इस सप्ताह अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर आतंकियों के हमले की कड़ी निंदा की। वहीं, भारत ने कहा कि वह अफगानिस्तान में धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों को जानबूझकर निशाना बनाए जाने पर काफी चिंतित है। हमले में हजारा समुदाय के 10 कामगारों की मौत हो गयी और 14 अन्य घायल हो गए। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट इन खोरेसान प्रोविंस (आईएसकेपी) ने इन लोगों पर हमला किया था। सुरक्षा परिषद ने आठ जून को अफगानिस्तान के बगलान-ए-मरकाजी में किए गए इस कायराना हमले की कड़ी निंदा की। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने अफगानिस्तान में धार्मिक और जातीय मूल के लोगों पर हमले को लेकर चिंता प्रकट की। घटना के शिकार हुए लोग बारूदी सुरंग ढूंढने के लिए एक संगठन के साथ काम कर रहे थे।

जरूरत के वक्त भारत की सहायता कर रहे हैं जैसे पिछले साल कोविड के दौरान उसने की थी- अमेरिकी अधिकारी का बयान

वाशिंगटन। अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा कि अमेरिका कोविड-19 की गंभीर होती दूसरी लहर के बीच जरूरत के वक्त में भारत की उसी प्रकार सहायता कर रहा है जिस तरह उसने मदद का हाथ बढ़ाया था जब वैश्विक महामारी के चलते यहां अस्पतालों पर बोझ बहुत बढ़ गया था। यूएसएड के प्रशासक के कोविड-19 कार्य बल कार्यालय के कार्यकारी निदेशक जेरेमी एम कोनीडिक ने सदन की विदेश मामले समिति की उपसमिति 'अंतरराष्ट्रीय विकास, अंतरराष्ट्रीय संगठन एवं एवं वैश्विक कॉर्पोरेट सामाजिक प्रभाव' को बताया कि रक्षा मंत्रालय के सहयोग से, यूएसएआईडी ने अहम चिकित्सीय आपूर्तियों को हवाई मार्ग से वहां पहुंचाया।

बलूचिस्तान में सैन्य कार्रवाई में मारे गए दो आतंकी, एक सैनिक की भी हुई मौत

कराची। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में खुफिया से मिली सूचना के आधार पर शुक्रवार को की गयी सैन्य कार्रवाई में दो आतंकवादी मारे गए जबकि मुठभेड़ में एक सैनिक की भी मौत हो गयी। पाकिस्तान की सेना के मीडिया विभाग ने एक बयान में बताया कि खरान जिले के हलमर्ग इलाके में सुरक्षा बलों ने अभियान चलाया और इस दौरान फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान के एक सैनिक की मौत हो गयी। बयान में कहा गया, ''हिंसा और आतंकवाद की विभिन्न घटनाओं में संलिप्त रहे दो आतंकवादी मारे गए और बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद किया गया।'' आतंकवादी और अलगाववादी आए दिन बलूचिस्तान प्रांत में आतंकी हमले करते हैं और सुरक्षा बलों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को निशाना बनाते हैं। इसी महीने की शुरुआत में अलग-अलग हमले में चार सैनिक मारे गए थे और आठ जवान घायल हो गए थे।

ब्रिटेन सरकार लॉकडाउन में और एक महीने की कर रही देरी: सूत्र

लंदन। ब्रिटेन सरकार कोविड-19 के नए मामलों में बढ़ोतरी और डेल्टा वैरिएंट के फैलने को लेकर चिंताओं के बीच इंग्लैंड में शेष प्रतिबंध हटाने में एक और महीने की देरी करने पर विचार कर रही है। सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी।
डेल्टा वैरिएंट के प्रसार पर चिंताओं के कारण 21 जून को इंग्लैंड में प्रतिबंधों को अनलॉक करने के अंतिम चरण में देरी के लिए सरकार को बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है, जो यूके में प्रमुख तनाव बन गया है। सरकार के रोडमैप में सामाजिक संपर्क की सभी कानूनी सीमाओं को 21 जून को हटाए जाने की उम्मीद है। डाउनिंग स्ट्रीट के सूत्रों ने बीबीसी को बताया कि सरकार द्वारा अभी लॉकडाउन पर अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है। एक स्रोत के अनुसार, 14 जून को होने वाली अंतिम घोषणा से पहले अभी भी डेटा की जांच की जा रही थी और सरकार इंग्लैंड के रोडमैप के चरण चार के लिए विकल्प- प्लूरल पर विचार कर रही थी। सूत्र ने बीबीसी को बताया, तारीख को पीछे धकेलने से टीकाकरण कार्यक्रम अधिक प्रभावी हो जाएगा, क्योंकि रोलआउट कम उम्र के समूहों में चला जाएगा।

चीन और अमेरिकी राजनयिकों के बीच हुई तीखी बहस, ड्रैगन ने कहा- आंतरिक मामलों में दखलअंदाजी न दे अमेरिका

बीजिंग। (एजेंसी)।

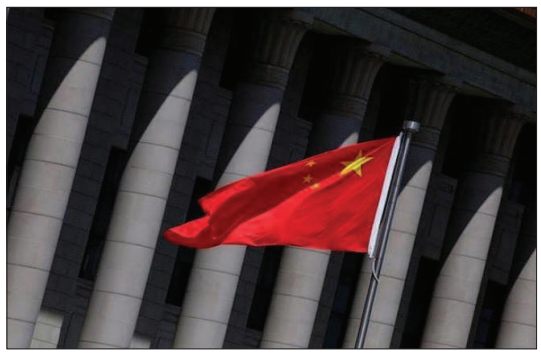

अमेरिका और चीन के शीर्ष राजनयिकों के बीच माना जा रहा है कि तीखी बहस हुई है जिसमें बीजिंग ने बताया कि उसने अमेरिका से कहा है कि वह उसके आंतरिक मामलों में दखलअंदाजी बंद करे। उसने कोविड-19 महामारी के उत्पत्ति स्थान मामले का राजनीतिकरण करने का अमेरिका पर आरोप लगाया। चीन के वरिष्ठ विदेश नीति सलाहकार यांग जिएची और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बीच शुक्रवार को फोन पर बातचीत हुई जिसमें हांगकांग में स्वतंत्रता पर अंकुश, शिंजियांग क्षेत्र में मुसलमानों को बड़े पैमाने पर हिरासत में रखने साहित अनेक मुद्दों पर बातचीत हुई। दरअसल सार्स सीओवी-2 के उत्पत्ति के स्थान संबंधी जांच की मांग चीन के लिए परेशानी की बात है,क्योंकि ऐसी अफवाहें हैं कि यह प्रयोगशाला में बनाया गया और वहां से वुहान में फैला।
यांग ने इन बातों को बकवास बताया और कहा कि चीन इन बातों से बेहद चिंतित है। सरकारी समाचार समिति शिन्हुआ की एक रिपोर्ट में यांग के हवाले से कहा गया,'' अमेरिका में कुछ लोग ने वुहान प्रयोगशाला से लीक होने संबंधी कहानियां बनाई है जिसे ले कर चीन बेहद चिंतित है। चीन अमेरिका से तथ्यों और विज्ञान का सम्मान करने, कोविड-19 की उत्पत्ति का राजनीतिकरण करने से बचने और महामारी से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग पर ध्यान केन्द्रित करने की अपील करता है।'' वहीं अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ब्लिंकन ने वायरस की उत्पत्ति स्थान को ले कर पारदर्शिता बरतने और सहयोग करने की जरूरत पर जोर दिया जिसमें (विश्व स्वास्थ्य संगठन) चीन में विशेषज्ञों की अगुवाई में दूसरे चरण की जांच शामिल है।

जो बाइडेन प्रशासन ने ट्रंप काल के एक सरकारी कार्यालय को किया बंद

सैन डिएगो। (एजेंसी)।

जो बाइडेन प्रशासन ने शुक्रवार को कहा कि उसने ट्रंप काल के एक सरकारी कार्यालय को बंद कर दिया है जो शरणार्थियों द्वारा किए गए अपराधों के पीड़ितों की मदद के लिए खोला गया था। यह कदम आव्रजकों या शरणार्थियों को अपराध से जोड़ने के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगातार प्रयासों को राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा खारिज किए जाने का संकेत देता है। ट्रंप ने जनवरी 2017 में अपने कार्यकाल के पहले हफ्ते में आव्रजन अपराध कार्य पीड़ित कार्यालय-वॉयस को एक शासकीय आदेश के माध्यम से स्थापित किया था। अमेरिकी आव्रजक एवं सीमा-शुल्क प्रवर्तन ने कहा कि वह वॉयस के स्थान पर 'अधिक व्यापक एवं समावेशी पीड़ित सहायता प्रणाली' शुरू कर रहा है। वॉयस के स्थान पर 'पीड़ित कार्य एवं सेवा लाइन' कार्यालय होगा जो लंबे समय से मौजूद सेवाओं को इसमें शामिल करेगा जिसमें शरणार्थी निरुद्ध केंद्रों में दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने के तरीके और आव्रजन मामलों में निहित स्वार्थों वाले वकीलों एवं अन्य के लिए एक अधिसूचना प्रणाली शामिल होगी। नये कार्यालय में अमेरिका में हिंसक अपराधों या मानव तस्करी के पीड़ितों के लिए निर्धारित संभावित वीजा प्राप्तकर्ताओं के लिए एक सेवा जोड़ी जाएगी।

तिब्बत के हर कोने में छाए हुए है चीनी राष्ट्रपति शी के पोस्टर, क्या नई चाल चल रहा ड्रैगन?

बीजिंग। (एजेंसी)।

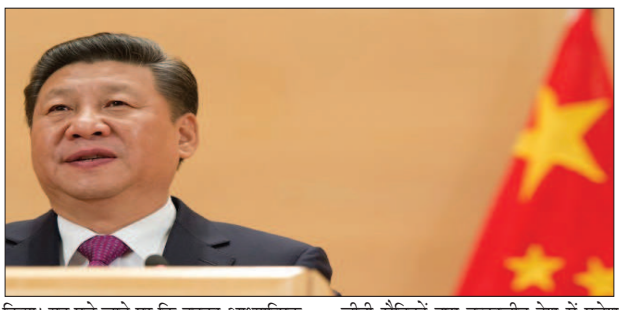

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पोस्टर अब तिब्बत के हर जगहों पर छाये हुए है। टीओआई में छपी एक खबर के मुताबिक, तिब्बत की राजधानी ल्हासा में केवल एक ही चीज सर्वव्यापी है और वो है चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और साथी नेताओं की तस्वीरें। अब सवाल है कि क्या तिब्बत पर कब्जा जमाए हुए चीन अब अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहता है? आपको बता दें कि चीन की न केवल तिब्बत बल्कि सीमा से लगने वाले अन्य देशों पर भी काफी तेज नजर बनी हुई है।
आपको बता दें कि, पिछले हफ्ते क्षेत्र के एक सरकारी दौरे में, एक रॉयटर्स पत्रकार ने कक्षाओं, सड़कों, धार्मिक संस्थानों, घरों और यहां तक की बौद्ध भिक्षु के शयनकक्ष में चीनी राष्ट्रपति शी के तस्वीरों को देखा गया है।बता दें कि इस दौरे पर एक दर्जन से अधिक अन्य पत्रकार भी गए थे। पांच दिवसीय यात्रा पर सरकार ने जिन नागरिकों और धार्मिक हस्तियों के साक्षात्कार की, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी और चीनी राष्ट्रपति शी के प्रति वफादारी का वादा किया। यह पूछे जाने पर कि उनका आध्यात्मिक गुरु कौन है, ल्हासा के जोखांग मंदिर में एक भिक्षु, जिसका नाम शी था। आपको बता दें कि शी की तस्वीरें लगभग सभी विजिट किए गए स्थलों पर दिखाई दिए गए। तिब्बती अध्ययन के विद्वान रॉबर्ट बार्नेट ने कहा, 'पोस्टर एक बड़े राजनीतिक शिक्षा कार्यक्रम के साथ मेल खाते हैं, जिसे 'पार्टी के प्रति आभार' की भावना कहा जाता है।' यात्रा के दौरान, सरकारी अधिकारियों ने सुझाव दिया कि चीनी झंडे के साथ ऐसी तस्वीरें तिब्बत में 'देशभक्ति की भावना' का संकेत देती है।
चीनी सैनिकों द्वारा तत्कालीन देश में प्रवेश करने और इसके प्रशासन को संभालने के बाद बीजिंग का कहना है कि उसने 1951 में तिब्बत को शांतिपूर्वक मुक्त कर दिया है। तिब्बती बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा, चीनी शासन के खिलाफ असफल विद्रोह के बाद 1959 में तिब्बत से भाग गए, और तब से धर्मशाला में एक निर्वासित सरकार की स्थापना की। रॉयटर्स ने 31 मई से 5 जून की यात्रा पर दलाई लामा की कोई तस्वीर नहीं देखी, जो पहले पूरे तिब्बत में घरों में आम थी।

विदेश मंत्री एस जयशंकर तीन दिवसीय यात्रा पर केन्या पहुंचे,कई मंत्रियों से करेंगे मुलाकात

नैरोबी। (एजेंसी)।

विदेश मंत्री एस जयशंकर शनिवार को तीन दिवसीय यात्रा पर केन्या पहुंचे। इस दौरान वह प्रमुख पूर्वी अफ्रीकी देश के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने के लिए कई बैठकें करेंगे। केन्या गणराज्य के विदेश मामलों के मुख्य प्रशासनिक सचिव (सीएएस) अबाबू-नामवाम्बा ने यहां पहुंचने पर जयशंकर का स्वागत किया। भारतीय उच्चायोग ने यहां ट्वीट किया, ''वह केन्या के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए कई बैठकें करेंगे, जिसकी शुरुआत वह विदेश कार्यालय के सीएस अम्ब रेशेल ओमामो के साथ आज (शनिवार को) बैठक करके करेंगे।'' वह केन्या के विदेश मंत्री के साथ भारत-केन्या संयुक्त आयोग की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जायेगी। संयुक्त आयोग की पिछली बैठक मार्च, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित हुई थी।
जयशंकर भारत-केन्या संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए केन्याई सरकार के अन्य मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। उनकी यात्रा से पहले नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने कहा था, ''विकास साझेदारी, दोनों देशों के बीच संबंधों का एक महत्वपूर्ण पक्ष है और यह आगे और गहरी होगी।'' मंत्री भारतीय मूल के समुदाय के साथ भी बातचीत करेंगे, जो दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु है।

केन्या में भारतीय मूल के लोगों का एक जीवंत समुदाय है, जिनकी संख्या वर्तमान में 80,000 है, जिसमें लगभग 20,000 भारतीय नागरिक शामिल हैं। भारत और केन्या वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हैं। वे राष्ट्रमंडल के सदस्य भी हैं। केन्या अफ्रीकी संघ का एक सक्रिय सदस्य है, जिसके साथ भारत के लंबे समय से संबंध हैं।

बाइडेन-पुतिन शिखर वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड 3,000 सैनिकों को करेगा तैनात

जिनेवा। स्विट्जरलैंड के प्राधिकारियों ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच अगले हफ्ते होने वाली शिखर वार्ता के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा के लिए जिनेवा शहर के वायु क्षेत्र को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित करने और इलाके में 3,000 सैनिकों तथा पुलिसकर्मियों को तैनात करने की योजना बनाई है। स्विट्जरलैंड की सात सदस्यीय कार्यकारी संस्था संघीय परिषद (फेडरल काउंसिल) ने शुक्रवार

को अस्थायी कदमों को मंजूरी दी जिसमें बुधवार को होने वाली शिखर वार्ता के दौरान देश की वायु सेना द्वारा वायु क्षेत्र की निगरानी करना और 1,000 सैनिकों को तैनात करना शामिल है। स्विट्ज़रलैंड के संघीय रक्षा विभाग ने एक बयान में कहा, ''उन लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना स्विट्जरलैंड की जिम्मेदारी है जिन्हें अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत विशेष सुरक्षा मिली है जैसे कि अमेरिका और रूस के राष्ट्राध्यक्ष।'' उसने बताया कि मंगलवार को सुबह आठ बजे से बृहस्पतिवार शाम पांच बजे तक रहने वाली इस पाबंदी से जिनेवा से उड़ान भरने वाले और यहां आने वाले विमानों की आवाजाही पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जिनेवा पुलिस विभाग की कमांडर कर्नल मोनिका बोनफांती ने शिखर वार्ता स्थल के बाहर संवाददाता सम्मेलन में कहा कि स्विट्ज़रलैंड के अन्य क्षेत्रों से 900 अतिरिक्त पुलिस अधिकारियों को बुलाया जाएगा। संघीय पुलिस कार्यालय के उप निदेशक स्टीफन थीमर ने बताया कि उनके कार्यालय को खतरे का कोई संकेत नहीं मिला है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि ''स्विट्ज़रलैंड और यूरोप में आतंकवादी खतरा अधिक रहता है।'' रक्षा विभाग ने बताया कि अतिरिक्त सैनिक विदेशी दूतों की रक्षा करेंगे और जिनेवा की क्षेत्रीय पुलिस को सहयोग देंगे। स्थानीय प्राधिकारियों ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि बाइडन की राष्ट्रपति के तौर पर पहली विदेश यात्रा के तहत होने वाली यह शिखर वार्ता 18वीं सदी के एक मैनर हाउस में होगी।

यूएन में बोला भारत, पाकिस्तान समेत सभी देशों के साथ 'सामान्य' दोस्ताना संबंध चाहता है देश

संयुक्त राष्ट्र। (एजेंसी)।

भारत ने कहा है कि वह पाकिस्तान समेत सभी देशों के साथ ''सामान्य'' दोस्ताना संबंध चाहता है और यह जिम्मेदारी इस्लामाबाद की है वह एक ''अनुकूल माहौल'' पैदा करे और अपने क्षेत्र का किसी भी तरीके से भारत के खिलाफ सीमापार आतंकवाद के लिए इस्तेमाल न होने दे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर आर मधुसूदन ने यह टिप्पणी शुक्रवार को '2020 के लिए सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट' पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में कीं। मधुसूदन ने महासभा में कहा, ''भारत, पाकिस्तान समेत सभी देशों के साथ सामान्य दोस्ताना संबंध चाहता है।
हमारा लगातार यह रुख रहा है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच कोई मसला है तो उसका हल द्विपक्षीय तथा शांतिपूर्ण रूप से निकाला जाना चाहिए और वो भी भय, शत्रुता और हिंसा से मुक्त माहौल में।'' उन्होंने कहा, ''यह जिम्मेदारी पाकिस्तान की है कि वह अपने क्षेत्र को किसी भी तरीके से भारत के खिलाफ सीमापार आतंकवाद के लिए इस्तेमाल न करने देकर विश्वसनीय, पुष्ट कार्रवाई करे और अनुकूल माहौल बनाए।'' इससे पहले संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने अपनी टिप्पणियों में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया था। जिस पर भारतीय अधिकारी ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान लगातार ऐसी हरकतों में शामिल है जो इस मंच के लिहाज से शोभा नहीं देतीं।
मधुसूदन ने कहा, ''यह साफ है कि यह प्रतिनिधिमंडल अब अंतरराष्ट्रीय समुदाय को मूर्ख नहीं बना पाएगा।'' उन्होंने कहा कि पाकिस्तान यूएनजीए के मंच का दुरुपयोग करना चाहता है और उसने ''एक बार फिर मेरे देश के आंतरिक मुद्दों को उठाया है।'' उन्होंने कहा कि भारत की संसद द्वारा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर लिए गए फैसले ''भारत के आंतरिक मामले'' हैं। भारत का अभी गैर-स्थायी

सदस्य के तौर पर सुरक्षा परिषद का दो साल का कार्यकाल है। भारत ने कहा कि 15 देशों की परिषद के सदस्य के तौर पर वह अन्य निर्वाचित सदस्यों के साथ कामकाज के तरीकों में सुधार लाने के अपने प्रयास जारी रखेगा।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य चुने गए यह 5 देश

संयुक्त राष्ट्र। (एजेंसी)।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शुक्रवार को पांच देशों ब्राजील, संयुक्त अरब अमीरात,अल्बानिया,घाना और गबोन को अस्थाई सदस्य निर्वाचित किया गया। पंद्रह सदस्यों वाले सुरक्षा परिषद की सदस्यता हासिल करने को बड़ी उपलब्धि के तौर देखा जाता है क्योंकि यह मंच देशों को सीरिया, यमन, माली और म्यांमा में संघर्ष से ले कर उत्तर कोरिया और ईरान से परमाणु खतरे तथा आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट और अलकायदा के हमलों के संबंध में मजबूती से अपनी बात रखने का मौका देता है। अल्बानिया पहली बार परिषद का सदस्य चुना गया है वहीं ब्राजील का परिषद में शामिल होने का यह 11वां मौका है। परिषद में अस्थाई सदस्य दो वर्ष के लिए चुना जाता है। अफ्रीका की दो सीटों के लिए त्रिपक्षीय मुकाबला था लेकिन सोमवार को कांगो ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी।
महासभा के अध्यक्ष वोल्कन बोज्कीर ने गुप्त मतदान के जरिए चुने गए देशों के नामों की घोषणा की और उन्हें बधाई दी। परिषद के पांच नए सदस्यों का कार्यकाल एक जनवरी से शुरू होगा और ये उन पांच देशों का स्थान लेंगे जिनका दो वर्ष का कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। ये पांच देश हैं- एस्टोनिया, नाइजर, सेंट विन्सेंट एंड ग्रेनाडियंस, ट्युनीशिया और वियतनाम। पांच नए अस्थाई सदस्य, परिषद के पांच स्थाई सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस तथा पिछले वर्ष चुने गए अस्थाई सदस्य भारत, आयरलैंड, केन्या, मेक्सिको और नॉर्वे के साथ मिल कर काम करेंगे।

ब्रिटेन की महारानी के जन्मदिन पर भारतवंशी कोविड-19 पेशेवर होंगे सम्मानित, जारी हुई लिस्ट

लंदन। (एजेंसी)।

ब्रिटेन की महारानी के जन्मदिन पर सम्मानित होने वालों की सूची में कोविड-19 रोधी टीके के परीक्षण के दौरान शामिल भारतवंशी स्वास्थ्य विशेषज्ञों और समुदाय की मदद करने वाले पेशेवरों के नाम शामिल हैं। यह सूची शुक्रवार शाम जारी की गयी। कोलकाता में जन्मी दिव्या चड्ढा मानेक को टीका के क्षेत्र में अनुसंधान, विकास और इसके बाद क्लिनिकल ट्रायल में भूमिका तथा महामारी के दौरान सेवाओं के लिए ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर (ओबीई) से सम्मानित किया गया है। मानेक वर्तमान में ब्रिटिश सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान (एनआईएचआर) क्लिनिकल रिसर्च नेटवर्क में बिजनेस डेवलपमेंट और मार्केटिंग की निदेशक हैं। मानेक युवावस्था में ही ब्रिटेन आ गयी थीं। उन्होंने कहा, ''यह सम्मान न सिर्फ मुझे बल्कि ब्रिटेन में टीका अनुसंधान में शामिल सभी लोगों को मान्यता देता है। जब मैं भारत से ब्रिटेन आयी थी तब मैं 18 साल की थी। मेरे पिता ने विमान का टिकट और 500 पाउंड दिए थे और कहा था = 'अच्छे बने रहो, अच्छा करो और कुछ अभूतपूर्व करो जिससे कि तुम महारानी से मिल सको'।

पिछले साल मैंने अपने पिता को खो दिया लेकिन यह सम्मान सच में ऐसा एहसास दिलाता है जैसे मैंने उनकी ओर से वाकई में कुछ अच्छा किया हो। इस सम्मान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।'' मानेक के अलावा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बाल संक्रमण विशेषज्ञ प्रोफेसर एंड्रयू पोलार्ड को विशेषकर कोविड-19 के दौरान जनस्वास्थ्य में सेवा और ऑक्सफोर्ड टीका समूह के निदेशक के तौर पर ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका टीका के विकास में भूमिका के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया। महारानी के जन्मदिन पर सम्मानित किये जाने वालों की सूची हर साल जारी की जाती है। सम्मानित होने वाले व्यक्तियों की 2021 की सूची में शामिल अन्य 30 से अधिक भारतवंशियों में ओबीई श्रेणी में जसविंदर सिंह राय, मेंबर्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर (एमबीई) की श्रेणी में देविना बनर्जी, अनूप जीवन चौहान, डॉ अनंतकृष्णन रघुराम के नाम शामिल हैं।

संपादकीय

शिक्षा का सफर

अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण के नतीजे जहां कुछ मोर्चों पर खुशी देते हैं, वहीं कुछ मोर्चों पर चुनौती भी पेश करते हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि उच्च शिक्षा में छात्राओं का नामांकन पिछले वर्षों में बढ़ा है। साल 2015-16 से 2019-20 तक पांच वर्षों में उच्च शिक्षा में महिला नामांकन में 18.2 फीसदी की वृद्धि हुई है, जबकि कुल नामांकन में 11.4 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी यह सर्वेक्षण भारत में महिला शिक्षा सुधार की गति दर्शाता है। वैसे हम इस मोर्चे पर ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे और हमें ऐसा करना ही चाहिए था, इसलिए यह प्रगति तुलनात्मक रूप से बेहतर भले लगे, पर समग्रता में पर्याप्त नहीं है। उच्च शिक्षा में महिलाओं के बढ़ते नामांकन से हमें अभिभूत नहीं होना चाहिए। अभी महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में लंबी खाई को पाटना है। पुरुषों के साथ मिलकर शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना है। अभी इतना जरूर कहा जा सकता है कि उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी उनकी बुनियादी मजबूती का संकेत है। शिक्षित महिलाएं ही श्रेष्ठ विकसित समाज का आधार बन सकती हैं। शिक्षा का यह मजबूत आधार महिला शिक्षा के साथ ही पुरुषों की शिक्षा को भी बल प्रदान करेगा और भारत की चमक बढ़ेगी। हालांकि, सर्वेक्षण में यह भी पाया गया है कि राष्ट्रीय महत्व के शिक्षा संस्थानों में छात्राओं की हिस्सेदारी कम है। सर्वेक्षण में यह भी पाया गया है कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमोंमें महिलाओं की भागीदारी अकादमिक पाठ्यक्रमों की तुलना में कम है। सर्वेक्षण स्पष्ट संकेत कर रहा है कि लड़कियों को राष्ट्रीय महत्व के शिक्षा संस्थानों में अपनी पैठ बढ़ानी चाहिए। ऊंचे सपने और परिश्रम से पढ़ाई के बूते राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में लड़कियों के लिए पर्याप्त जगह बन सकती है। लेकिन आज के समय में भी अगर ज्यादातर महिलाएं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के प्रति लगाव नहीं दर्शा रही हैं, तो चिंता वाजिब है। आर्थिक, सामाजिक मजबूती के लिए लड़कियों को रोजगार के जोखिम और मेहनत भरे पाठ्यक्रमों में भी जोर आजमाना चाहिए। अकादमिक पढ़ाई से एक स्तर तक ही लाभ है, जबकि व्यावसायिक पढ़ाई उद्यम के ज्यादा मौके प्रदान करती है। इसके अलावा, भारत में पीएचडी में अगर एक प्रतिशत छात्र-छात्राओं का भी नामांकन नहीं हो पा रहा है, तो हमें सोचना होगा। पीएचडी का आकर्षण क्यों कम हुआ है? क्या पीएचडी से वाजिब नौकरी मिल जाती है? प्रस्तुत सर्वेक्षण में कुल 1,019 विश्वविद्यालयों, 39,955 कॉलेजों और 9,599 एकल संस्थानों ने भाग लिया है, यह दायरा बड़ा होना चाहिए। खुशी की बात है, उच्च शिक्षा में नामांकित कुल छात्रों में से अनुसूचित जाति के छात्र 14.7 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के 5.6 प्रतिशत और 37 प्रतिशत छात्र अन्य पिछड़ा वर्ग से थे। 5.5 प्रतिशत छात्र मुस्लिम अल्पसंख्यक और 2.3 प्रतिशत छात्र अन्य अल्पसंख्यक समुदायों से थे। एक बात गौर करने की है कि भारत में 78.6 प्रतिशत से अधिक कॉलेज निजी क्षेत्र द्वारा चलाए जा रहे हैं, जो कुल नामांकन का 66.3 प्रतिशत है। भारत जैसे देश में ज्यादातर शिक्षा का काम सरकार के जिम्मे ही होना चाहिए, अगर ऐसा होता, तो शायद हमारे यहां शिक्षा की स्थिति ज्यादा बेहतर और समावेशी होती।

राजनीतिक अग्निपरीक्षा से गुजर रही कांग्रेस

राजकुमार सिंह

लगभग दो साल से पूर्णकालिक अध्यक्ष के बिना ही जीवन की सबसे बड़ी राजनीतिक अग्निपरीक्षा से गुजर रही कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी तो पता नहीं फिर से पार्टी के राजा बनने का मन कब बना पायेंगे, लेकिन उनकी युवा ब्रिगेड के खास सदस्य माने जाते रहे किरदारों ने एक-एक कर किनारा करना ही शुरू नहीं कर दिया, बल्कि उस भाजपा का दामन भी थामना शुरू कर दिया है, कांग्रेस-मुक्त भारत जिसका घोषित मिशन है। पिछले साल मार्च में कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका देने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, जिन्हें राहुल के सबसे करीब माना जाता रहा। सिंधिया अकेले नहीं गये। इतने कांग्रेस विधायक भी ले गये कि कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार जाती रही और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में फिर से भाजपा सरकार की वापसी हो गयी। मध्य प्रदेश के बाद पिछले साल कोरोना काल में ही राजस्थान में भी ऐसे ही सत्ता परिवर्तन की पटकथा लिखी जा रही थी। मध्य प्रदेश में सिंधिया की तरह राजस्थान में सचिन पायलट को भी लगता है कि मुख्यमंत्री पद पर उनकी दावेदारी थी, जिसे पुराने खिलाड़ी अशोक गहलोत ने हड़प लिया। तीखे तेवर दिखाने के बाद भी सचिन ने कांग्रेस की लक्ष्मण रेखा क्यों पार नहीं की—इसकी कई व्याख्याएं की गयीं। सचिन खेमे से धर्मनिरपेक्षता के प्रति प्रतिबद्धता के नाम पर भाजपा में न जाने की बात दोहरायी जाती रही तो गहलोत खेमा उनके पास पर्याप्त विधायक न होने का तंज कसता रहा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के रुख को लेकर आशंकित भाजपा रणनीति के तहत मौन ही रही। नतीजतन मध्य प्रदेश में सरकार गंवाने के लिए चौतरफा आलोचना का पात्र बना कांग्रेस आलाकमान समय से सक्रिय होकर सचिन को मनाने और अंततः राजस्थान में सरकार बचाने में सफल रहा। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि पूरे घटनाक्रम से जरूरी सबक सीखा गया। ऐसा इसलिए कि लंबा समय गुजर जाने के बावजूद कांग्रेस संगठन और गहलोत सरकार में सचिन समर्थकों को अभी तक एडजस्ट नहीं किया गया। मध्य प्रदेश और राजस्थान के घटनाक्रम का एक जरूरी सबक यह भी था कि अन्य राज्यों में अंतर्कलह के मुखर होने से पहले ही अपना घर ठीक कर लिया जाये। आलाकमान द्वारा गठित समिति के समक्ष पिछले सप्ताह पंजाब कांग्रेस के विभिन्न गुटों की पेशी तथा इसी सप्ताह उत्तर प्रदेश कांग्रेस के एक बड़े चेहरे जितिन प्रसाद का भाजपा में शामिल हो जाना बताता है कि कांग्रेस जनता के बीच ही नहीं, खुद कांग्रेसियों के बीच जबरदस्त अविश्वास के दौर से गुजर रही है। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनावों में केंद्रीय सत्ता गंवाने से ठीक पहले और उसके बाद भी कांग्रेस से भाजपा में पलायन कम नहीं हुआ, लेकिन तब उसे ऐसे पुराने कांग्रेसियों की सत्ता लोलुपता मान लिया गया, जो बिना सत्ता रह ही नहीं सकते। यह भी कि राजनीतिक हवा के साथ रुख बदलना जिनकी फितरत थी। बेशक पुराने दिग्गजों का खासकर संकटकाल में दल बदलना किसी भी दल के लिए बड़ा झटका ही है, लेकिन कांग्रेस में ताजा भगदड़ ज्यादा चिंताजनक इसलिए भी है, क्योंकि भागने वाले या भागने को तैयार किरदार वे हैं, जिनके सहारे राहुल गांधी कांग्रेस का कायाकल्प करना चाहते थे। तमाम तर्क और सलाह के बावजूद राहुल गांधी तो मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री नहीं बने, लेकिन आखिरी वर्षों में ही सही, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, सचिन पायलट और आरपीएन सिंह सरीखों को यह अवसर भी दिया गया । इसके बावजूद राहुल गांधी के ये सिपहसालार एक के बाद एक कांग्रेस को डूबता जहाज मान कर सत्ता के तेज रफ्तार स्टीमर भाजपा पर छलांग लगाने को उतावले नजर आ रहे हैं तो इन्हें अवसरवादी सत्ता लोलुप करार देने और भाजपा को कोसने के अलावा कांग्रेस आलाकमान को आत्मविश्लेषण करने की भी जरूरत है। पुरानों-नयों के बीच सत्ता संघर्ष हर दल में रहता ही है। यह जिम्मेदारी स्वाभाविक ही आलाकमान की होती है कि वह बदलती पीढ़ियों और अनुभव एवं जोश में सही संतुलन बना कर चले। अगर राहुल गांधी अपने इन्हीं सिपहसालारों के सहारे नयी कांग्रेस और बेहतर राजनीतिक संस्कृति बनाना चाहते हैं तो उन्हें इनके संरक्षण में भी खड़ा होना चाहिए। मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह सरीखे खुर्राट कांग्रेसियों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के इर्दगिर्द चक्रव्यूह रचा, पर राहुल मूकदर्शक बने रहे। मुख्यमंत्री पद से शुरू संघर्ष जब राज्यसभा सदस्यता के रास्ते विधायक दल में बगावत और राज्य सरकार पर संकट में तबदील हुआ, तब भी राहुल सक्रिय होने के बजाय खुद रूठे-से नजर आये। जाहिर है, वह लोकतांत्रिक-राजनीतिक व्यवहार कम, राजवंशी अहमन्यता अधिक थी। सिंधिया और राज्य सरकार गंवाने के झटके का इतना असर तो अवश्य हुआ कि राजस्थान में सचिन पायलट को लक्ष्मण रेखा लांघने से पहले ही मना लिया गया। इस तरह वहां कांग्रेस सरकार भी बच गयी, लेकिन दोनों खेमों में मतभेद और मनभेद मिटा कर संतुलन-समन्वय बनाने के लिए अभी तक कुछ भी नहीं किया गया। न सचिन को सम्मानजनक स्थान मिला, न ही उनके समर्थकों को सरकार-संगठन में हिस्सेदारी। ऐसे में जितिन प्रसाद के पाला बदलते ही सचिन समर्थकों के फिर से मुखर होने के लिए सिर्फ उन्हें दोष कैसे दिया जा सकता है? दो लोकसभा और एक विधानसभा चुनाव हारने वाले जितिन को पश्चिम बंगाल का चुनाव प्रभार सौंपा गया, लेकिन चुनाव परिणाम के महीने भर बाद उन्होंने खुद ही कमल थाम लिया। निश्चय ही यह कांग्रेस आलाकमान की व्यक्ति और राजनीति की समझ पर सवालिया निशान भी लगाता है। पंजाब कांग्रेस के जिस अंतर्कलह को सुलझाने के लिए आलाकमान को अब समिति बनाने की सुध आयी, वह भी पुराना है। क्रिकेटर से राजनेता और भाजपाई से कांग्रेसी बने नवजोत सिंह सिद्धू तो मंत्री पद से इस्तीफे के बाद से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। सिद्धू कई बार आलाकमान से मिले और कई बार कैप्टन से मतभेद दूर होने की चर्चाएं भी चलीं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। अब जबकि विधानसभा चुनावों में साल भर भी नहीं रह गया है और कैप्टन के विरुद्ध असंतोष बड़े पैमाने पर मुखर होने लगा है तो आलाकमान की तंद्रा टूटी है। कैप्टन विरोधियों की संख्या तो निश्चय ही बढ़ी है, लेकिन उनमें से शायद ही किसी का अपने चुनाव क्षेत्र के बाहर कोई प्रभाव हो। फिर इनमें से कुछ तो आम आदमी पार्टी के भी संपर्क में हैं, जिसकी चुनावी संभावनाएं कुछ राजनीतिक प्रेक्षकों को बेहतर नजर आ रही हैं। वैसे भी चुनाव से आठ-नौ महीने पहले बड़ा जोखिम उठाना साहस कम, दुस्साहस ज्यादा साबित हो सकता है। हां, समय से असंतोष सुलझा कर कांग्रेस अपनी चुनावी संभावनाओं को अवश्य बेहतर बना सकती थी। पिछले साल से ही जी-23 के नाम से मशहूर कुछ नेताओं ने कांग्रेस में संगठनात्मक सुधार का अभियान चला रखा है। इनके अगुआ माने जाने वाले गुलाम नबी आजाद की बाबत कहा गया कि राज्यसभा सदस्यता की समाप्ति को लेकर वह ज्यादा परेशान थे। कांग्रेस में संगठनात्मक सुधार तो अभी तक नजर नहीं आया, पर तमिलनाडु से आजाद की राज्यसभा में वापसी की संभावनाएं अवश्य प्रबल हो गयी हैं। इतने भर से कांग्रेस सुधर जायेगी या फिर कोई दूसरा नेता संगठनात्मक सुधार का मोर्चा संभालेगा—जल्द पता चल जायेगा। हां, इतना तय है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से शुरू हुआ कांग्रेस से पलायन जितिन प्रसाद पर ही रुकने वाला नहीं है। अगर कांग्रेस आलाकमान ने समय रहते पर्याप्त राजनीतिक परिपक्वता और कौशल नहीं दिखाया तो झारखंड में झामुमो-कांग्रेस सरकार बनवाने में भूमिका निभाने वाले आरपीएन सिंह से लेकर नवजोत सिंह सिद्धू तक कई चेहरे देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी को अलविदा कहते नजर आयेंगे।

आज के ट्वीट

सहायता

कोविड-19 महामारी के कारण अपने पति को खो चुकी विधवा महिलाओं को भी राज्य सरकार द्वारा एकमुश्त एक लाख रूपये की सहायता अनुदान के रूप में दी जाएगी। साथ ही, ऐसी विधवाओं को प्रतिमाह डेढ़ हजार रूपये विधवा पेंशन दी जाएगी। इसके लिये आयु वर्ग एवं आय की कोई भी सीमा नहीं होगी। --मु. अशोक गहलोत

ज्ञान गंगा

भारतीय संस्कृति

श्रीराम शर्मा आचार्य

भारतीय संस्कृति सबके लिए सभी भांति विकास का अवसर देती है। किसी अन्य धर्म संस्कृति में ऐसा प्रावधान नहीं है। उनमें एक ही इष्टदेव और एक ही तरह के नियम मानने की परंपरा है। इसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। करता है तो दंडनीय होगा। एक उद्यान में कई तरह के पौधे और फूल उगते हैं। इससे बगीचे की शोभा ही बढ़ती है। यही बात विचार उद्यान के संदर्भ में स्वीकार की जा सकती है। इसमें अनेक प्रयोग परीक्षणों के लिए गुंजायश रहती है और सत्य को सीमाबद्ध कर देने से उत्पन्न अवरोध की हानि नहीं उठानी पड़ती। नास्तिकवादी लोगों के लिए भी भारतीय संस्कृति के अंग बने रहने की छूट है, जबकि उनके लिए धर्मो के द्वार बंद हैं। भारतीय संस्कृति की दूसरी विशेषता है कर्मफल की मान्यता। पुनर्जन्म के सिद्धांत में जीवन को अवांछनीय माना गया है और मरण की उपमा वस्त्र परिवर्तन से दी गई है। कर्मफल की मान्यता नैतिकता और सामाजिकता की रक्षा के लिए नितांत आवश्यक है। मनुष्य की चतुरता अद्भुत है। वह सामाजिक विरोध और राजदंड से बचने के अनेक हथकंडे अपनाकर कुकर्मरत रह सकता है। ऐसी दशा में किसी सर्वज्ञ सर्व समर्थ सत्ता की कर्मफल व्यवस्था का अंकुश ही उसे सदाचरण की मर्यादा में बांधे रह सकता है। परलोक की, स्वर्ग नरक की, पुनर्जन्म की मान्यता समझाती है कि आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कर्म का फल भोगना पड़ेगा। दुष्कर्म का लाभ उठाने वाले यह न सोचें कि उनकी चतुरता सदा काम देती रहेगी और वे पाप के आधार पर लाभान्वित होते रहेंगे। इसी प्रकार जिन्हें सत्कर्मो के सत्परिणाम नहीं मिल सके हैं उन्हें भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगले दिनों वे भी अदृश्य व्यवस्था के आधार पर मिल कर रहेंगे। संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म समयानुसार फल देते रहते हैं। इस मान्यता को अपनाने वाला न तो निर्भय होकर दुष्कर्मो पर उतारू हो सकता है और न सत्कर्मो की उपलब्धियों से निराश। अन्य धर्म जहां अमुक मत का अवलंबन अथवा अमुक प्रथा प्रक्रिया अपना लेने मात्र से ईश्वर की प्रसन्नता और अनुग्रह की बात कहते हैं, वहां भारतीय धर्म में कर्मफल की मान्यता को प्रधानता दी गई है और दुष्कर्मो का प्रायश्चित करके क्षति पूर्ति करने को कहा गया है।

विपक्ष की छवि को धूमिल बनाते नकारात्मक विरोध

डॉ. दिलीप अग्निहोत्री

लोकतंत्र के प्रभावी संचालन में विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण है लेकिन इसका सकारात्मक होना भी आवश्यक है। नकारात्मक विरोध अंततः विपक्ष की छवि को ही धूमिल बनाते है। इसका अपरोक्ष लाभ सत्ता पक्ष को ही मिलता है। यहां बात केवल संख्या बल तक ही सीमित नहीं है। स्वतन्त्रता के बाद कई दशक तक देश की राजनीति में कॉग्रेस का वर्चस्व था। तब जनसंघ, सोशलिस्ट और बाद में भाजपा संख्या बल के हिसाब से बहुत कमजोर हुआ करते थे। एक समय यह भी था कि लोकसभा में भाजपा के मात्र दो सदस्य थे। लेकिन उसने अपने वैचारिक आधार को कभी कमजोर नहीं होने दिया। तब विपक्ष की दलीलें सरकार को बेचैन बनाती थी क्योंकि उनमें राष्ट्रीय हित की नसीहत हुआ करती थी। राष्ट्रीय संकट के अनेक पड़ाव आये, तब यही विपक्ष सरकार के साथ हुआ करता था। लेकिन विगत छह वर्षों में विपक्ष की राजनीति का आधार नकारात्मक ही रहा है। ये अपने संगठन की दम पर सरकार विरोधी एक भी आंदोलन या सत्याग्रह नहीं कर सके। हर समय ऐसा लगता रहा जैसे ये नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं कर सके है। इन्हें जहां भी नरेंद्र मोदी के विरोध का धुआं उठता दिखाई दिया, ये वहीं दौड़ गए। ऐसा करते समय अपनी मर्यादा या लाभ हानि पर भी विचार नहीं किया। असहिष्णुता व सम्मान वापसी से शुरू हुई यह राजनीति आज तक जारी है। कुछ दिन पहले कॉग्रेस पर कथित रूप से टूल किट जारी करने का आरोप लगा था। इसमें कितनी सच्चाई थी, यह जांच का विषय हो सकता है। इसलिए टूलकिट को फिलहाल छोड़ देते हैं। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के बाद जिस प्रकार की राजनीति हुई, उसके आधार पर क्या निष्कर्ष निकाला जाए। क्या सबकुछ सुनियोजित नहीं लगता, क्या भारत का विपक्ष पूरी दुनिया में बिल्कुल अलग दिखाई नहीं दे रहा था। क्या सरकार के विरोध की धुन में राष्ट्रीय सम्मान को धूमिल करने का जाने अनजाने प्रयास नहीं हुआ था। कोरोना से विकसित देशों को भारत के मुकाबले औसत अधिक नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन वहां के विपक्ष ने इसे राजनीति का अवसर नहीं माना। सेंट्रल विस्टा के निर्माण को रोकने का ट्वीट अभियान चलाया गया। यह दिखाने का प्रयास हुआ कि सरकार का खजाना खाली है, इसलिए सेंटर विस्टा निर्माण का धन भी आपदा प्रबंधन में लगाना चाहिए। जबकि सरकार का कहना था कि इस निर्माण व कोरोना के बीच कोई संबन्ध नहीं है। सरकार के पास आपदा प्रबंधन के लिए धन की कोई कमी नहीं है। बाद में पता चला कि केंद्र सरकार के करीब दो दर्जन विभाग निजी भवनों में चलते हैं। अनेक भवन राजनीति के चर्चित लोगों के है। इनको हजारों करोड़ रुपये किराया मिलता है। सेंट्रल विस्टा बनने के बाद ये सभी कार्यालय वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। इसलिए विरोध हो रहा था। सरकार को घेरने के लिए हरिद्वार कुंभ का मुद्दा उठाया गया। बाद में उजागर हुआ कि कुम्भ के कारण कोरोना नहीं फैला था। आपदा के पूरे दौर में कैसे कैसे ट्वीट किए गए। ऐसा करने वाले लोग स्वयं भी सत्ता में रह चुके है। तब उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी बढ़ा दी थी। प्रश्न केवल ऑक्सीजन व वेंटिलेटर तक सीमित नहीं था। इनके संचालन हेतु मैनपावर भी जरूरी था। ट्वीट करने वालों को बताना चाहिए कि उनके शासन में कितने मेडिकल कॉलेज खुले थे। इस मामले में नरेंद्र मोदी के सात वर्ष उन सभी पर भारी है। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद जितने मेडिकल कॉलेज बने उससे करीब दुगुने योगी आदित्यनाथ सरकार के समय बनाये जा रहे है। वैक्सीन पर जमकर हंगामा किया गया। कॉंग्रेस शासित राज्यों को केंद्र से जितनी वैक्सीन मिली थी, उसका भी ठीक से इस्तेमाल नहीं किया गया। राजस्थान में बड़ी संख्या में वैक्सीन कचरे में फेंके गए। पंजाब सरकार पर निजी अस्पतालों को वैक्सीन बेचने के आरोप है। पंजाब में वैक्सीन का बड़ा घोटाला सामने आया है। वह डोज जिसे अठारह से चवालीस साल के आयु वर्ग के लिए चार सौ रुपए में खरीदा गया उसे एक हजार रुपए से अधिक प्रति डोज की दर से प्राइवेट अस्पतालों को बेचा गया था। छत्तीसगढ़ में भी वैक्सीन की हर तीन में से एक शीशी के बर्बाद होने का आंकड़ा है। विपक्ष के निशाने पर दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, राजस्थान, बंगाल सरकार निशाने पर नहीं थी। जबकि इन राज्यों की स्थिति सर्वाधिक खराब थी। अन्य गंभीर बीमारियों के वैक्सिनेशन के संबन्ध में कॉंग्रेस को अपना अतीत भी देखना चाहिए। पोलियो, स्मॉल पॉक्स,हैपेटाइटिस बी की वैक्सीन के लिए देशवासियों ने दशकों तक इंतजार किया था। इस गति से वैक्सिनेशन में चालीस वर्ष और लगते। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही वैक्सीनेशन के लिए मिशन मोड में काम किया। कॉंग्रेस के समय भारत में वैक्सीनेशन का कवरेज सिर्फ साठ प्रतिशत था। मोदी सरकार ने मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया। छह वर्ष में वैक्सीनेशन कवरेज नब्बे प्रतिशत हो गया। नकारात्मक राजनीति के इस दौर में नरेंद्र मोदी के संबोधन ने सकारात्मक विचार को प्रोत्साहित किया। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव द्वारा वैक्सीन टीका लगवाना भी सकारात्मक कदम था। क्योंकि वैक्सीन पर भ्रम फैलाने में उनके उत्तराधिकारी भी किसी से कम नहीं थे। ये दोनों ही प्रकरण सकारात्मक सन्देश देने वाले थे। नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में पिछले कुछ समय से जारी नकारात्मक राजनीति का उल्लेख किया। ऐसा करने वालों ने हर कदम पर भ्रम फैलाया। ऑक्सीजन से लेकर वैक्सिनेशन तक इसके दायरे में थे। लेकिन इन बातों को पीछे छोड़ते हुए नरेन्द्र मोदी ने सभी राज्यों में वैक्सिनेशन व गरीबों को राशन वितरित करने का संकल्प दोहराया। यह उनके सकारात्मक रुख की अभिव्यक्ति थी। संकट काल में सरकार कुछ अच्छा करे तो उसका समर्थन करना चाहिए। सरकारी मशीनरी चिकित्सकों आदि का उत्साह बढ़ाना चाहिए। इससे अंततः विपक्ष की छवि बेहतर बनती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो सका। अस्सी करोड़ गरीबों को निःशुल्क राशन देने का निर्णय सराहनीय था। अस्सी करोड़ लोगों को पहले आठ महीने राशन देना सामान्य बात नहीं थी। दूसरी लहर में भी यह योजना संचालित की गई है। विपक्ष को देखना चाहिए कि उसकी नकारात्मक राजनीति से देश की जनता प्रभावित नहीं है। वैक्सीन पर नकारात्मक राजनीति के बाद भी तेईस करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। गैर भाजपा मुख्यमंत्री भी नकारात्मक राजनीति में बहुत आगे थे। अपने प्रदेश के हित की जगह उन्हें यह परेशानी थी कि सफलता का श्रेय केंद्र सरकार को ना मिल जाये। इस कारण इन राज्यों में स्थिति बिगड़ी है।

ये राज्य उचित व्यवस्था में विफल रहे। पूछा जाने लगा कि सबकुछ भारत सरकार ही क्यों नहीं तय कर रही। राज्य सरकारों को छूट क्यों नहीं दी जा रही। लॉकडाउन की छूट राज्य सरकारों को क्यों नहीं मिल रही है। वन साइज डज नॉट फिट फॉर ऑल की दलील दी गई।

आज का राशिफल

मेष बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। रुपए पैसे के लेन-देन में सावधानी रखें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी।

वृषभ पारिवारिक व व्यावसायिक समस्याएं रहेंगी। उदर विकार या त्वचा के रोग से पीड़ित रहेंगे। आय और व्यय में संतुलन बनाकर रखें। जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। वाहन प्रयोग में सावधानी रखें।

मिथुन सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। व्यावसायिक योजना सफल होगी। रुपए पैसे के लेन-देन में सावधानी रखें। मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी। व्यर्थ के तनाव मिलेंगे।

कर्क बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। जारी प्रयास सफल होंगे। वाणी की सौम्यता बनाये रखें। प्रणय संबंध प्रगाढ़ होंगे। वाहन प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है।

सिंह प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। पिता या उच्चाधिकारी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। भाई या पड़ोसी का सहयोग मिलेगा। ससुराल पक्ष से लाभ मिलेगा। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा।

कन्या जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि मिलेगी। रुका हुआ कार्य सम्पन्न होगा। यात्रा में अपने सामान के प्रति सचेत रहें चोरी या खोने की आशंका है। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी।

तुला राजनैतिक महात्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। व्यावसायिक योजना सफल होगी। प्रेम प्रसंग प्रगाढ़ होंगे। वाहन प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है।

वृश्चिक आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। उदर विकार या त्वचा के रोग से पीड़ित रहेंगे। आय के नए स्त्रोत बनेंगे। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी। प्रियजन भेंट संभव।

धनु पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। रुपए पैसे के लेन-देन में सावधानी रखें। जारी प्रयास सफल होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। प्रणय संबंध प्रगाढ़ होंगे। धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी।

मकर दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। आय के नवीन स्त्रोत बनेंगे। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न लें। कार्यक्षेत्र में रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा।

कुम्भ व्यावसायिक दिशा में किए गए प्रयास सफल होंगे। अनावश्यक कष्टों का सामना करना पड़ेगा। रुका हुआ कार्य सम्पन्न होगा। नेत्र विकार की संभावना है। ससुराल पक्ष से लाभ होगा। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी।

मीन पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। सृजनात्मक कार्यों में हिस्सा लेना पड़ सकता है। पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। अनावश्यक कार्यों में खर्च करना पड सकता है।

मरुस्थलीकरण (रेगिस्तान का फैलना) आज विश्व भर में एक विकट समस्या बन गया है। उससे बड़ी संख्या में मनुष्य प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि रेत का साम्राज्य बढ़ने से अन्न का उत्पादन घटता है और अनेक प्राकृतिक तंत्रों की धारण क्षमता कम होती है। पर्यावरण भी उसके कुप्रभावों से अछूता नहीं रह पाता। मरुस्थलीकरण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है, जिससे विश्व भर के शुष्क क्षेत्रों में उपजाऊ जमीन अनुपजाऊ जमीन में बदल रही है। मानव गतिविधियां और भौगोलिक परिवर्तन, दोनों इसके लिए जिम्मेदार हैं। शुष्क क्षेत्र उन इलाकों को कहते हैं, जहां उतनी बारिश नहीं होती कि घनी हरियाली पनप सके। विश्व के कुल स्थल भाग का लगभग 40 प्रतिशत, अथवा 5.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर शुष्क है। मरुस्थलीकरण इन्हीं शुष्क भागों में अधिक देखने में आता है।

मिट्टी हो रही रेत

भारत का 69.6 प्रतिशत भूभाग (22.83 करोड़ हेक्टेयर) शुष्क माना गया है। यद्यपि इन शुष्क इलाकों की उत्पादकता काफी कम है, फिर भी दूध, मांस, रेशे, चमड़ा आदि के उत्पादन में वे काफी योगदान देते हैं। देश की आबादी का एक बहुत बड़ा भाग शुष्क इलाकों में रहता है। भारत में 17.36 करोड़ हेक्टेयर, अथवा देश के कुल क्षेत्रफल का 53 प्रतिशत, मरुस्थलीकरण से प्रभावित है। ये इलाके अक्सर सूखे की चपेट में भी रहते हैं। सूखा मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को तेज कर देता है। राजस्थान का पश्चिमी भाग और गुजरात का कच्छ जिला लगभग सदा सूखे की गिरफ्त में रहते हैं।

मनुष्य तथा उसके पालतू पशु सदा से ही रेगिस्तानी इलाकों में रहते आ रहे हैं। विश्व के अन्य शुष्क इलाकों की तुलना में भारत के शुष्क इलाकों में मानव आबादी का दबाव कहीं ज्यादा है। भारत के पास विश्व के कुल स्थल भाग का मात्र 2.4 प्रतिशत है, लेकिन कुल मानव आबादी का 16.67 प्रतिशत भारत में रहता है। इतना ही नहीं, भारत में विश्व में मौजूद चरागाहों का मात्र 0.5 प्रतिशत ही है, पर यहां विश्व में मौजूद मवेशियों का 18 प्रतिशत पलता है। मनुष्य और मवेशियों का यह असहनीय दबाव मरुस्थलीकरण को बढ़ावा दे रहा है। थार रेगिस्तान के भीतरी भागों तक में खेती और पशुपालन का प्रसार हो रहा है। रेगिस्तानी इलाकों में पानी की सीमित उपलब्धि वानस्पतिक उत्पादकता की सीमा बांध देती है। वहां वर्षा भी बड़े ही अनियमित ढंग से होती है, जिससे अन्न के उत्पादन में बड़ी-बड़ी अनियमितताएं देखी जाती हैं। इससे पैदा हुई अन्न की किल्लत से गरीब तबके के लोग सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। जीवित रहने के लिए उन्हें रेगिस्तान की वनस्पति पर अत्यधिक निर्भर होना पड़ता है। जैसे-जैसे मनुष्यों और मवेशियों की संख्या बढ़ती जाती है, यह निर्भरता भी बढ़ती है। किसी भी प्राकृतिक-तंत्र की धारण क्षमता सीमित होती है। इस सीमा का उल्लंघन होने पर वह तंत्र बिखरने लगता है। शुष्क इलाकों का प्राकृतिक तंत्र भी मनुष्य द्वारा डाले गए दबाव से आखिरकार चरमरा जाता है। यदि समय रहते इस विघटनकारी प्रक्रिया को रोका नहीं गया, तो सारा तंत्र रेगिस्तान की भेंट चढ़ जाता है, अथवा अत्यधिक चराई और लकड़ी के लिए पेड़ों की छंटाई के कारण उस तंत्र में उपयोगी पौधों की तादाद घट जाती है। उनका स्थान अनुपयोगी और अखाद्य पौधे ले लेते हैं। नतीजा यह होता है कि वह तंत्र अब पहले से भी कम संख्या में मनुष्यों और मवेशियों को पोषित कर पाता है। यही दुश्चक्र मरुस्थलीकरण को गति देता है।

यद्यपि शुष्क इलाकों में बारिश कम होती है, पर जो बारिश होती है, वह काफी तेज और तूफानी ढंग की होती है। इससे इन इलाकों में बारिश अक्सर बाढ़ का रूप धारण करके उपजाऊ मिट्टी को बहा ले जाती है। एक अनुमान के अनुसार बंजर इलाकों में हर हेक्टेयर क्षेत्र से हर साल पानी के कटाव से 16.35 टन मिट्टी बह जाती है। इससे देश के बहुत बड़े-बड़े इलाकों में खड्ड और नाले बन गए हैं और वे खेती के लिए निकम्मे हो गए हैं। काफी इलाकों में रेत के टीलों ने अधिकार जमा लिया है। इस प्रकार अनुपयोगी बनी जमीन को पुन: उपजाऊ बनाने का काम वहां की मिट्टी की जिजीविषा शक्ति पर निर्भर करता है, पर यदि समय रहते कदम न उठाए गए, तो यह मिट्टी ही लुप्त हो जाती है। बार-बार आने वाला सूखा मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को त्वरित कर देता है, यद्यपि सूखे का प्रभाव क्षणभंगुर ही होता है।

अभी हाल तक हर गांव में नदी-तालाब होते थे, जिनका पानी फसल उगाने के लिए पर्याप्त था। गांव के गोचरों में मवेशियों के लिए चारा पैदा होता था। आसपास के जंगलों से चूल्हे के लिए लकड़ी मिल जाती थी। आज इन्हीं गांवों का हाल बिलकुल बदल गया है। नदी-तालाब सूख गए हैं, अथवा उनमें पानी बहुत कम रह गया है। जो जलाशय बचे हैं, उनमें से कई तो इतने प्रदूषित हो गए हैं कि उनका पानी पीने लायक नहीं रह गया है।

गांव की स्त्रियों को पानी, चारा और ईंधन लाने के लिए मजबूरन कोसों चलना पड़ रहा है। यह दुखद स्थिति गांवों तक सीमित नहीं है, अनेक शहरों की भी यही दशा है। मिट्टी के कटाव का एक अन्य दुष्परिणाम यह है कि पानी के साथ बह आई मिट्टी जलाशयों में जमा होकर उनके जलधारण क्षमता को घटा रही है। इससे बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो जाती है और लाखों लोगों को हर साल बारिश के मौसम में बेघर होना पड़ता है। हमारे देश में ऐसे व्यक्तियों की तादाद बहुत ज्यादा है जिनके लिए बारिश का मौसम अभिशाप बनकर आता है, क्योंकि वह मौत, बीमारी और तबाही का पैगाम भी साथ लाता है। बड़ी-बड़ी पनबिजली योजनाओं के सरोवरों में मिट्टी भर जाने से उनसे निर्मित बिजली की मात्रा घटी है और इन योजनाओं की आयु कम हो गई है।

मिट्टी को पहुंचे नुकसान से कृषि की उत्पादनशीलता में जो कमी आई है, उसे लगभग 23,200 करोड़ रुपए आंका गया है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि हमारे जैसे निर्धन देश में बढ़ती आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने की जरूरत है, न कि घटाने की।

मरुस्थलीकरण एक बहुआयामी समस्या है जिसके जैविक, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक आदि अनेक पक्ष हैं। इसलिए उससे निपटने में केंद्र और राज्य सरकारों की अनेक संस्थाएं योगदान दे रही हैं। मरुस्थलीकरण से लड़ रहे मुख्य मंत्रालयों में शामिल हैं पर्यावरण और वन मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय।

सन 1985 में राष्ट्रीय भूमि-उपयोग एवं परती विकास परिषद को उच्चतम नीति-निर्धारक एवं समायोजक एजेंसी के रूप में गठित किया गया। यह परिषद देश भर की जमीनों के प्रबंध से जुड़ी समस्याओं पर विचार करती है तथा नीतियां बनाती है। इस परिषद के अध्यक्ष स्वयं प्रधान मंत्री हैं। यह परिषद राष्ट्रीय भूमि-उपयोग एवं संरक्षण बोर्ड, राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड और राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी-विकास बोर्ड के कामों की देखरेख करती है। राज्य स्तर पर राज्य-स्तरीय भूमि-उपयोग बोर्ड गठित किए गए हैं। इनके अध्यक्ष संबंधित राज्य के मुख्य मंत्री होते हैं। ये बोर्ड भूमि विकास संबंधी कार्यक्रम चलाते हैं।

पिछले कई सालों से शोध संस्थाएं कृषि विश्वविद्यालयों के सहयोग से मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों पर गहन अनुसंधन कार्यों में लगी हुई हैं। इन अनुसंधानों की प्राथमिकता रही है मरुस्थलीकरण रोकना और सूखा-पीड़ित इलाकों की उत्पादकता बढ़ाने की कार्यक्षम विधियां विकसित करना। इन अनुसंधान कार्यों को आर्थिक मदद देने के लिए केंद्रीय और राज्य स्तर की अनेक अनुसंधान संस्थान गठित किए गए हैं। इनमें शामिल हैं, हैदराबाद का केंद्रीय शुष्क खेती अनुसंधान संस्थान, जोधपुर का केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, करनाल का केंद्रीय क्षारीय जमीन अनुसंधान संस्थान, देहरादून का केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान, झांसी का भारतीय वन एवं चरागाह अनुसंधान संस्थान और नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के परिसर में स्थित जल प्रौद्योगिकी केंद्र। देहरादून के भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद के मार्गदर्शन में अनेक शोध संस्थाएं शुष्क प्रदेशों के वनों के पुनरुद्धार के कार्य में लगी हैं तथा इन वनों की उत्पादकता में वृद्धि लाने के तरीके खोज रही हैं। ये सब संस्थाएं शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियां विकसित करने के साथ-साथ कर्मचारियों को विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण भी देती हैं। इन संस्थाओं के कार्यों को समर्थन देने के लिए काफी धनराशि उपलब्ध कराई गई है और नीतिमूलक संरचनाएं एवं विधि-कानून बनाए गए हैं।

सन 1992 में ब्राजील के रियो द जनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन में विश्व समुदाय ने मरुस्थलीकरण रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए। 15 जून 1994 को इस संधि को कानूनी स्वरूप दिया गया। भारत ने उसे 17 दिसंबर 1996 को अनुमोदित किया। इस संधि का उद्देश्य है मरुस्थलीकरण रोकना तथा मरुस्थलीकरण और सूखे के कारण मानव समुदायों पर पड़ रहे विपरीत प्रभावों को कम करने के लिए सभी देशों के बीच सभी स्तरों पर सहयोग बढ़ाना। मरुस्थलीकरण रोकने के भगीरथ कार्य में पारंपरिक ज्ञान की अहम भूमिका है क्योंकि वह समयसिद्ध ही नहीं है, बल्कि साधारण जनता की दैनंदिन की समस्याओं को सुलझाने में कामयाब भी रहा है। इनमें से कुछ पारंपरिक विधियों का संक्षिप्त विवरण आगे दिया जा रहा है।

थार रेगिस्तान में वर्ष के कुछ ही महीने फसल उगाने के लिए उपयुक्त होते हैं। अत: वहां के लोगों ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए खेती के साथ पशुपालन भी करना सीख लिया है। गर्मियों में वे बाजरा आदि खुरदुरे अनाजों की खेती करते हैं, जिन्हें बहुत कम पानी चाहिए होता है। लेकिन पालीवाल नामक एक काश्तकार समुदाय वर्षाजल संचित करके सर्दियों की फसल भी उगाने में सफल हुआ है। इस विधि को खदीन प्रणाली कहते हैं। आज 500 से भी ज्यादा छोटे-बड़े खदीन हैं जो 12,140 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित कर रहे हैं। बिहार में इससे मिलता-जुलता एक दूसरा तरीका है जिसे अहर कहा जाता है।

ये हैं दुनिया के रहस्यमयी प्राणी

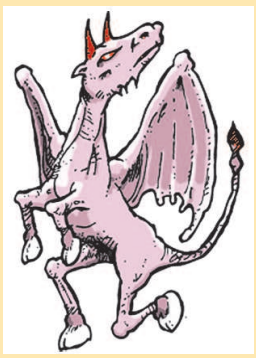

जर्सी डेविल

जर्सी डेविल के बारे में 1800 से लेकर 20वीं सदी तक कई तरह की बातें की जाती रही। इसे न्यू जर्सी के दक्षिणी क्षेत्र में देवदार वृक्ष के जंगल में देखे जाने की बात सामने आई थी। जर्सी डेविल के बारे में कहा जाता था कि उसके दो पैर, चमगादड़ की तरह पंख और घोड़े की तरह मुंह था। इस विचित्र प्राणी को लेकर यह प्रचलित था कि एक चुड़ैल जब अपने 13वें बच्चे को जन्म दे रही थी उस समय उसने शैतान को जगा दिया था। इस कारण जन्म लेते ही इस बच्चे का विचित्र ढंग से रूप बदल गया।

फ्लैटवुड मॉन्स्टर

फ्लैटवुड मॉन्स्टर भी किसी परलौकिक प्राणी की तरह दिखाई देता था। वेस्ट वर्जीनिया में ब्रेक्सटन काउंटी के फ्लैटवुड कस्बे में 12 सितंबर, 1952 को इसे देखा गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार वह 10 फीट लंबा था और उसका चेहरा लाल रंग का था। उसका विचित्र चेहरा और आंखें इंसानों जैसी नहीं थीं। ऐसा लगता था कि वह गहरे रंग की स्कर्ट पहने हुए है।

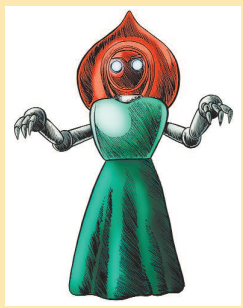

लिजर्डमैन

दुनिया के सबसे डरावने विचित्र प्राणियों में अमेरिका का लिजर्डमैन भी है। साउथ कैरोलिना की ली काउंटी के स्वाम्पलैंड क्षेत्र में इसे 29 जून, 1988 को देखा गया था। हरी त्वचा वाले इस विचित्र प्राणी की लंबाई 7 फीट 2 इंच लंबी थी। रिपोर्ट्स के अनुसार लिजर्डमैन के हर पैर में तीन अंगूठे और हर हाथ में तीन अंगुलियां थीं। वह दीवारों और सीलिंग पर चढ़ जाता था। एक प्रमाण यह भी है कि उसने एक कार को भी नुकसान पहुंचाया था। वह इतना ताकतवर था कि उसने कार तक को तोड़ दिया था।

डोवर डीमन

इस विचित्र और डरावने प्राणी को अमेरिका में देखा गया था। मैसाचुसेट्स के डोवर टाउन में यह 1977 में 21 और 22 अक्टूबर को दिखाई दिया था। इसके विचित्र रूप के कारण इसके एलियन या किसी प्रयोग का कोई हिस्सा होने के अनुमान लगाए जाते रहे। वह हाइब्रिड एलियन भी हो सकता था। कुछ लोगों का कहना है यह किसी दूसरे लोक से आया था। डोवर डीमन का सिर बड़ा था, आंखें ऑरेंज कलर की और हाथ-पैर पतले दिखाई देते थे। बताया जाता है कि यह बिना बालों का था। इसमें फेशियल फीचर्स बहुत कम थे। यह विचित्र प्राणी लगभग तीन फीट लंबा था। डोवर डीमन सांप की तरह फुफकारता और बाज की तरह चीखता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह किसी दूसरे ग्रह से आया होगा या जैविक कारणों से धरती के ही किसी जीव का आकार बदल गया होगा।

गोटमैन

बकरी और इंसान के फीचर्स लिए यह विचित्र जीव पहली बार अमेरिका में देखा गया था। इसके बारे में पहली रिपोर्ट 1957 में आई थी। एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार उसने बालों और सींग वाला एक दैत्य जैसा दिखने वाला प्राणी देखा था। इसे फॉरेस्टविले और अपर मार्लबोरो के प्रिंस जॉर्ज काउंटी में देखा गया था। यह 1962 तक छिपा रहा लेकिन एक दर्जन बच्चों और दो वयस्क लोगों की हत्या कर दी। यह लोगों पर कुल्हाड़ी से हमला करता था और शवों को कई टुकड़ों में काट डालता था।

चिकित्सा उपकरणों, अन्य सामान की कीमतों में हस्तक्षेप से बचे राज्य:एमटीएआई

नई दिल्ली: मेडिकल टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एमटीएआई) ने कहा है कि राज्यों को चिकित्सा उपकरणों और अन्य उत्पादों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप से बचना चाहिए। एमटीएआई ने कहा कि इस बारे में फैसला सिर्फ राष्ट्रीय औषधि मूल्य नियामक को ही लेना चाहिए। एमटीएआई शोध आधारित चिकित्सा प्रौद्योगिकी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। एमटीएआई के चेयरमैन एवं महानिदेशक पवन चौधरी ने बयान में कहा कि विभिन्न राज्यों द्वारा कोविड-19 के आवश्यक सामान मसलन पीपीई किट और एन95 मास्क की कीमतों को नियंत्रित करने के आदेश से आपूर्ति संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं। चौधरी ने कहा, हम महामारी के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। सरकार और उद्योग मिलकर इस स्थिति से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है। ऐसे समय में उद्योग से चर्चा के बिना कोई निर्णय लेने से असमंजस की स्थिति पैदा होगी। उन्होंने कहा कि केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र ने अलग-अलग समय में कीमतें तय की हैं। इसके कोई उत्पाद देश में भिन्न-भिन्न कीमतों पर बिकने का जोखिम पैदा हो गया है।

आईपीओ के लिए बाध्य एलआईसी ने अपने प्रतिष्ठित लोगों के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दी

मुंबई। देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने किसी के द्वारा अपने प्रतिष्ठित लोगों के अनाधिकृत उपयोग या दुरुपयोग को लेकर सार्वजनिक चेतावनी जारी की है। उनके ट्विटर हैंडल के अनुसार, एलआईसी ने किसी भी वेबसाइट, प्रकाशन हाउस या डिजिटल संस्थाओं को बिना पूर्व अनुमति के अपना लोगो प्रकाशित करने से रोक दिया है। 65 वर्षीय एलआईसी, जो जल्द ही अपने आईपीओ के लिए जा रही है, ने शुक्रवार को एक पोस्ट में अपने आधिकारिक लोगो का दुरुपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कानूनी या नागरिक कार्रवाई की चेतावनी दी है। साधारण लेकिन लोगों में जीवन के प्रतीक के रूप में जीवन बीमा के दो ढाल वाले हाथ होते हैं, जो इसकी सुरक्षा का संकेत देते हैं, इसके नीचे संस्कृत किंवदंती है-भगवद् गीता से व्युत्पन्न योगक्षेमं वहम्याहं, और नरीमन पॉइंट पर एलआईसी मुख्यालय दक्षिण मुंबई में इसे योगक्षेम भी कहा जाता है। सोशल मीडिया पर एलआईसी की चेतावनी में कहा गया है- एलआईसी पब्लिक अलर्ट-एलआईसी के लोगो का अनधिकृत उपयोग। एलआईसी लोगो का उपयोग किसी भी वेबसाइट, प्रकाशन सामग्री और डिजिटल पोस्ट में नहीं किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सिविल और आपराधिक सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एलआईसी 1956 में स्थापित हुई थी, जिसकी देश में 68.90 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी है। इस साल अक्टूबर के आसपास एक आईपीओ के लिए जाने की योजना है, जैसा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल अपने बजट भाषण में घोषित किया था। एलआईसी के सूत्रों का कहना है कि बीमा योजनाओं और जनता के लिए छोटी या लंबी अवधि के निवेश के अवसरों के एक विशाल पोर्टफोलियो के अधिकारी कहते हैं कि यहां तक कि कुछ बेईमान एजेंट, स्वयंभू बीमा सलाहकार और बाहरी लोग भी भोले-भाले ग्राहकों को लुभाने के लिए अवैध रूप से इसके लोगो का दिखावा करते पाए गए हैं।

ऋण, जमा वृद्धि के मामले में बैंक ऑफ महाराष्ट्र सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नंबर वन

नई दिल्ली । बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम) ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान ऋण और जमा वृद्धि के लिहाज से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। बीओएम द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2020-21 में उसने सकल अग्रिम में 13.45 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, और इसके तहत राशि 1.07 लाख करोड़ रुपए रही। इसके बाद पंजाब एंड सिंध बैंक का स्थान रहा, जिसने मार्च 2021 में खत्म हुए वित्त वर्ष के दौरान 67,811 करोड़ रुपए के कुल ऋण के साथ 8.39 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। जमा राशि जुटाने के लिहाज से बीओएम लगभग 16 प्रतिशत की वृद्धि के साथ देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक से भी आगे रहा, जिसने 13.56 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। हालांकि, कुल मिलाकर एसबीआई का जमा आधार बीओएम के 1.74 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले 36.81 लाख करोड़ रुपए या 21 गुना अधिक है। इसी प्रकार चालू खाता बचत खाता में बीओएम ने 24.47 प्रतिशत वृद्धि हासिल की जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सर्वाधिक रही। यह बैंक की कुल देनदारी का 54 प्रतिशत रहा। वर्ष के दौरान बीओएम का कुल कारोबार 14.98 प्रतिशत बढ़कर 2.81 लाख करोड़ रुपए रहा। वित्त वर्ष 2020- 21 में बैंक आफ महाराष्ट्र का एकल शुद्ध लाभ 42 प्रतिशत बढ़कर 550.25 करोड़ रुपए रहा जो कि इससे पिछले वित्त वर्ष में 388.58 करोड़ रुपए रहा था। संपत्ति गुणवत्ता में भी बैंक ने अच्छी सफलता हासिल की है। मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां तेजी से घटकर 7.23 प्रतिशत रह गई जो कि एक साल पहले 12.81 प्रतिशत पर थी। निवल एनपीए भी एक साल पहले के 4.77 प्रतिशत से घटकर मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष में 2.48 प्रतिशत रह गया।

विमान सेवा कंपनी एयर एशिया इंडिया की सेल, किराया 1,177 रुपए से शुरू

नई दिल्ली: निजी किफायती विमान सेवा कंपनी एयरएशिया इंडिया ने देश में उड़ान आरंभ करने की 7वीं वर्षगांठ पर 'सेवेनटैस्टिक सेल% की घोषणा की है जिसके तहत किराया 1,177 रुपए से शुरू हो रहा है। एयरलाइन ने आज एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि विशेष सेल के तहत टिकट 12 जून से 14 जून तक बुक कराए जा सकेंगे। ऑफर 01 अगस्त 2021 या उसके बाद की यात्रा के लिए ही लागू होगा। किसी भी माध्यम से बुकिंग कराकर ग्राहक सेल का लाभ उठा सकते हैं। कंपनी की नई वेबसाइट 'एयरएशियाडॉटकोडॉटइन' से टिकट बुक कराने वाले ग्राहकों के लिए 'बुकफास्टफ्लाईफ्री' के नाम से एक प्रतियोगिता भी रखी गई है। एयरएशिया इंडिया ने 12 जून 2014 को देश में उड़ानों का परिचालन शुरू किया था। वर्तमान में इसके गंतव्यों में 17 शहर शामिल हैं। कंपनी के पास 32 एयरबस ए320 विमान हैं। ऑफर के तहत सबसे सस्ते किराए वाले मार्गों में गुवाहाटी-कोलकाता और चेन्नई-हैदराबाद (1,177 रुपए से), हैदराबाद-चेन्नई, बेंगलुरु-चेन्नई और बेंगलुरु-चेन्नई (1,377 रुपए से), कोलकाता-गुवाहाटी और दिल्ली-जयपुर (1,477 रुपए से), बेंगलुरु-पुणे, इंफाल-गुवाहाटी और चेन्नई-मुंबई (1,577 रुपए से) और मुंबई-चेन्नई 1,677 रुपए से शामिल है।

सीबीआईसी का राज्य नोड विकसित करने के लिए आंध्र ने 1,448 करोड़ रुपये मंजूर किए

अमरावती। आंध्र प्रदेश सरकार ने एक विशेष प्रयोजन वाहन एनकेआईसीडीएल (एनआईसीडीआईटी कृष्णापट्टनम इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड) बनाने के लिए 1,448 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जिसमें केंद्र सरकार की इक्विटी के साथ-साथ विकास को स्थापित करने, बढ़ावा देने और चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (सीबीआईसी) का कृष्णापटनम इंडस्ट्रियल नोड को सुविधा प्रदान करने के लिए है। एपीआईआईसी के मुख्य अभियंता कार्यालय से शुक्रवार को एक बयान में कहा गया कि एसपीवी का गठन आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन (एपीआईआईसी) और नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) द्वारा किया गया है। नोट में कहा गया है, विकास कार्य 2,500 एकड़ (लगभग) की सीमा में फैले हुए हैं, जो आंध्र प्रदेश राज्य में 2040 तक लगभग 10 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करेंगे। औद्योगिक नोड में खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक, कपड़ा और पहनने वाले परिधान, रसायन, दवा और विद्युत उपकरण, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑप्टिकल उत्पादों के निर्माण की उम्मीद है। इन क्षेत्रों को इस क्षेत्र में तेजी से विकास के समर्थक के रूप में पहचाना गया है। बयान में कहा गया है, कृष्णापट्टनम औद्योगिक नोड को विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ विकसित किया जा रहा है जिसमें सड़कों, पुलों, उपयोगिताओं, एसटीपी, सीईटीपी और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, प्रशासनिक भवन, बिजली आपूर्ति प्रणाली और जल आपूर्ति प्रणाली शामिल हैं। इस बीच, राज्य सरकार ने परियोजना निविदा दस्तावेज को न्यायिक पूर्वावलोकन वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ-साथ जनता से टिप्पणियां और सुझाव प्राप्त करने के लिए अपलोड किया।

कोविड राहत वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कटौती, वैक्सीन पर 5 प्रतिशत टैक्स बरकरार

नई दिल्ली।
कोविड-19 के इलाज के लिए आवश्यक वस्तुओं और दवाओं पर कम शुल्क लगाने की मांग के बीच, जीएसटी परिषद ने शनिवार को कई कोविड-राहत वस्तुओं की दरों को मौजूदा 12 से 18 प्रतिशत के स्तर से घटाकर पांच प्रतिशत करने का फैसला किया। हालांकि परिषद ने वैक्सीन को लेकर कर की दर को पांच प्रतिशत पर बरकरार रखा है। जीएसटी परिषद की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि परिषद ने मंत्रिसमूह (जीओएम) की सिफारिशों के साथ जाने के लिए सहमति व्यक्त की है, जो शनिवार को परिषद में एकल बिंदु एजेंडा रहा। उन्होंने कहा कि विभिन्न कोविड राहत चिकित्सा वस्तुओं पर कर की दर कम कर दी गई है, जबकि टीकों पर 5 प्रतिशत जीएसटी दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सीतारमण ने स्पष्ट किया कि वैक्सीन की दरों में कोई बदलाव नहीं किए जाने पर भी आम लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि टीकाकरण मुफ्त में उपलब्ध कराया जा रहा है। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार 75 प्रतिशत वैक्सीन खरीद रही है और उस पर जीएसटी भी भर रही है। लोगों को सरकारी अस्पतालों में जो ये 75 प्रतिशत वैक्सीन फ्री में उपलब्ध कराई जा रही है, जनता पर उसका कोई असर नहीं होगा। कोविड राहत उपायों के हिस्से के रूप में, जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक में रेमडेसिविर इंजेक्शन पर जीएसटी दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत और मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन पर टैक्स 5 प्रतिशत निर्धारित कर दिया गया है। परिषद ने ब्लैक फंगस के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं की दरों को भी घटाकर शून्य स्तर पर ला दिया है। यानी ब्लैक फंगस की बीमारी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। विशेष शुल्क में कटौती 30 सितंबर, 2021 तक लागू रहेगी। सीतारमण ने कहा कि हालांकि जीओएम ने अगस्त तक दरों में कटौती की सिफारिश की थी, मगर परिषद ने इसे सितंबर के अंत तक रखने का फैसला किया है। इसके बाद फैसला किया जाएगा कि उन जरूरी वस्तुओं की दरों में कटौती को विस्तार दिए जाने की आवश्यकता है या नहीं। उन्होंने कहा कि कोरोना टीकों पर 5 प्रतिशत जीएसटी रहेगा। केंद्र घोषणा के अनुसार, 75 प्रतिशत वैक्सीन खरीदेगा और उसका जीएसटी भी चुकाएगा, लेकिन जीएसटी से होने वाली आमदनी का 70 प्रतिशत राज्यों के साथ साझा किया जाएगा। एक अन्य बड़े कदम में, एम्बुलेंस पर जीएसटी की दर पिछले 28 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दी गई है। इसी तरह टॉसीलिजुमैब और एंफोटेरेसिन बी आदि दवाओं पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। मंत्री ने कहा कि 30 सितंबर 2021 तक कोरोना राहत और प्रबंधन में उपयोग की जा रही निर्दिष्ट वस्तुओं पर जीएसटी दरों को तय कर दिया गया है। कोविद-19 के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टॉसीलिजुमैब पर कर की दर को भी माफ कर दिया गया है। इस पर पिछली टैक्स दर 5 प्रतिशत थी। इसके अलावा, वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली परिषद ने यह भी निर्णय लिया कि कोविड के इलाज के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और फार्मा विभाग (डीओपी) द्वारा अनुशंसित किसी भी अन्य दवा पर कर की दर 5 प्रतिशत रखी जाएगी। जीवन रक्षक उपकरणों और उत्पादों के मामले में, जिसकी कम उपलब्धता ने पूरे देश में बहुत दहशत पैदा की है, कर की दर कम किए जाने पर कुछ राहत जरूर मिलेगी।

औद्योगिक उत्पादन में मजबूती के लिए कोविड-19 टीकाकरण की प्रगति को महत्वपूर्ण मानते हैं विशेषज्ञ

नई दिल्ली:

कोविड प्रभावित घरेलू अर्थव्यवस्था में औद्योगिक उत्पादन की रफ्तार में घटबढ़ जारी रहने के बीच बाजार विश्लेषकों कहा कहना है कि बाजार में मांग में सुधार और औद्योगिक गतिविधियों में मजबूती के लिए टीकाकरण की रफ्तार और संक्रमण पर नियंत्रण जरूरी है। सरकार द्वारा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के कल जारी आंशिक आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि कहने को सालाना आधार पर 134 प्रतिशत रहीं जो इसी वर्ष मार्च की तुलना में नरमी का संकेत देती है। सरकार ने कहा है कि पिछले साल अप्रैल में देशव्यापी कठोर लॉकडाउन के मद्देनजर औद्योगिक उत्पादन जिस तरह प्रभावित हुआ था उसके देखते हुए उसके साथ इस साल अप्रैल के आंकड़ों की तुलना व्यावहारिक नहीं है। औद्योगिक उत्पादन की अप्रैल 2021 की वृद्धि दर के आंकड़े पर निवेश परामर्श कंपनी मिलवुड केन इंटरनेशनल के संस्थापक एवं सीईओ नीश भट्ट ने कहा कि इस बार के आंकड़ों की तुलना पिछले साल अप्रैल से नहीं की जा सकती क्योंकि उस समय देश के अधिकांश भागों में कठोर लाकडाउन लागू था। भट ने कहा कि इस वर्ष अप्रैल की औद्योगिक वृद्धि मार्च की तुलना में 13 प्रतिशत कम रही। 'कोविड की दूसरी लहर का उद्योग धंधे पर असर पड़ा है। यह अप्रैल के आंकड़ों में झलक भी रहा है।' उन्होंने कहा कि कोविड टीकाकरण एक अच्छे खासे स्तर पर पहुंच जाने, कोरोना वायरस संक्रमण के काबू में आने, सरकारों की ओर से जायज कारोबार को जारी रखने की अनुमति दिए जाने के बाद ही औद्यागिक कामकाज में मजबूती के साथ तेजी लौटेगी। रियल एस्टेट बाजार का अनुसंधान करने वाली फर्म नाइट फ्रैंक के निदेशक (अनुसंधान) विवेक राठी ने भी कहा, 'हमारा मानना है कि आगे के दिनों में कोविड-19 टीकाकरण अभियान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। इससे उभोक्ताओं का विश्वास बढ़ेगा और मांग में तेजी आएगी। इसी से उत्पादन क्षमताओं का उपयोग और औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर में सुधार हो सकेगा। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की प्रमुख अर्थशास्त्री माधवी अरोड़ा ने कहा कि तुलना का आधार अनुकूल होने के कारण इस बार अप्रैल की औद्योगिक वृद्धि में 134 प्रतिशत का जबर्दस्त उछाल दिख रहा है जबकि गतिविधियां कमजोर हुई हैं। उन्होंने कहा कि मार्च, 2021 की तुलना में अप्रैल का औद्योगिक उत्पादन 12 प्रतिशत बढ़ा। महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों में स्थानीय स्तर पर लाकडाउन का उत्पादन पर असर दिखा है। महाराष्ट्र का देश के विनिर्माण क्षेत्र के सकल मूल्यवर्धन (विनिर्माण जीवीए) में 18 प्रतिशत का योगदान है। ' माधवी का अनुमान है कि 'यदि यह मान लें कि कोविड-19 अधिकतम प्रकोप इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही तक ही सीमित रहेगा और आबादी के बड़े हिस्से को पहली छमाही तक टीका लग चुका होगा तो मांग के उभरने से दूसरी छमाही में विनिर्माण और कुल मिलाकर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में सुधार दिखने लगेगा। उनका कहना है कि कोविड-19 की पहली लहर के बाद आर्थिक हाल में सुधार का ग्राफ अंग्रेजी के 'के' आकार यानी उतार चढ़ाव भरा रहा। श्रम बाजार पर इसका बुरा और विखंडनकारी प्रभाव दिखा। राजकोषीय प्रोत्साहन पर्याप्त से कम प्रभावकारी रहे। उनकी राय में आगे भी आर्थिक गतिविधियों में सुधार में पूंजी और लाभ की भूमिका ही ज्यादा होगी और उसमें श्रम बाजार और मजदूरी की दशा में सुधार शायद ही दिखे।' सरकार ने अप्रैल माह के औद्योगिक उत्पादन (आईआईपी) के पूर्ण आंकड़े जारी नहीं करने का फैसला किया है। कोविड-19 महामारी की वजह से लागू लॉकडाउन के चलते पिछले साल भी सरकार ने अप्रैल महीने के आईआईपी आंकड़े जारी नहीं किये थे। पिछले साल जून में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने कारखाना उत्पादन पर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की वजह से औद्योगिक उत्पादन पर पड़े प्रभाव के कारण आईआईपी आंकड़ों को रोक लिया गया था। इस साल भी अप्रैल के पूर्ण आंकड़े जारी नहीं किये जा रहे हैं। इस साल अप्रैल में आईआईपी 126.6 अंक रहा जो कि 2019 अप्रैल के करीब-करीब बराबर ही है। हालांकि, पिछले साल अप्रैल के मुकाबले यह 134 प्रतिशत की बढ़त दर्शाता है, क्योंकि पिछले साल अप्रैल में औद्योगिक गतिविधियां काफी कुछ बंद थी।

वित्तवर्ष 2021 में डीएलएफ की बिक्री 24 प्रतिशत बढ़कर 3,084 करोड़ रुपये की हुई

नयी दिल्ली,

रियल्टी प्रमुख डीएलएफ ने पिछले वित्तवर्ष में 3,084 करोड़ रुपये की आवासीय संपत्तियों की बिक्री की, जो वित्तवर्ष 2019-20 में हुई बिक्री से 24 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। महामारी के बावजूद कंपनी को पूर्ण और आवासों के लिए बेहतर मांग देखने को मिली। निवेशकों को दी गई प्रस्तुति के अनुसार, कंपनी की बिक्री बुकिंग वित्तवर्ष 2019-20 में 2,485 करोड़ रुपये की हुई थी। डीएलएफ ने कहा, वित्तवर्ष की पहली तिमाही की खामोशी के बावजूद वित्तवर्ष के लिए 3,084 करोड़ रुपये की नई बिक्री हुई। कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने के लिए देशव्यापी लॉकडाऊन के कारण वित्तवर्ष 2020-21 की जून तिमाही के दौरान आवास की बिक्री बुरी तरह प्रभावित हुई। डीएलएफ ने कहा, आवासीय मांग ने वित्तवर्ष 2021 के उत्तरार्द्ध के दौरान मजबूत प्रदर्शन किया। वित्तवर्ष 2022 की प्रथम तिमाही लॉकडाउन प्रतिबंधों के कारण प्रभावित हो सकता है। कंपनी को गुरुग्राम में अपनी स्वतंत्र मंजिल वाले आवासों के लिए अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। प्रस्तुति के अनुसार, डीएलएफ ने पिछले वित्तवर्ष के दौरान 51.2 लाख वर्ग फुट सहित 2,169 इकाइयों के लिए कब्जा पत्र जारी किए। शुक्रवार को, डीएलएफ ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए 480.94 करोड़ रुपये का एकीकृत शुद्ध मुनाफा दर्ज किया। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 1,857.76 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था। समीक्षाधीन तिमाही के दौरान कंपनी की कुल आय बढ़कर 1,906.59 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 1,873.80 करोड़ रुपये थी।

वित्तवर्ष 2020-21 में, डीएलएफ ने पिछले साल की समान अवधि में हुए 583.19 करोड़ रुपये के शुद्ध घाटे के मुकाबले 1,093.61 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा अर्जित किया। पिछले वित्तवर्ष में कुल आय घटकर 5,944.89 करोड़ रुपये रह गई, जो वित्तवर्ष 2019-20 में 6,888.14 रुपये थी।

इंडिया पावर को वित्तवर्ष 2021 में 27 करोड़ रुपए का मुनाफा

नई दिल्ली:

विद्युत वितरण कंपनी इंडिया पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तवर्ष में 26.66 करोड़ रुपए कर शुद्ध मुनाफा हुआ जा एक साल पहले से 60 प्रतिशत अधिक है। वित्तवर्ष 2019-20 में उसे 16.69 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। कोलकाता की इस कंपनी पश्चिम बंगाल को आसनसोल-रानीगंज क्षेत्र में 618 वर्ग किलोमीटर में फैले इलाके में वितरण का लाइसेंस है। यह औद्योगिक, वाणिज्यिक और घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली प्रदान करती है। कंपनी ने शनिवार को कहा ने शनिवार को कहा वर्ष के दौरान कंपनी की कुल आय 518.37 करोड़ रुपये थी। कंपनी ने तुलना के लिए पिछले आंकड़े का खुलासा नहीं किया। इंडिया पावर ने कहा कि वित्त वर्ष की पहली दो तिमाहियों के दौरान महामारी और लॉकडाउन के प्रभाव के बावजूद वर्ष 2020-21 में इसकी बिक्री में 20 लाख यूनिट की वृद्धि हुई। इंडिया पावर के पूर्णकालिक निदेशक सोमेश दासगुप्ता ने कहा, ''प्रतिस्पर्धी कीमतों पर बिजली खरीदने की हमारी क्षमता से लागत बचत हुई।''

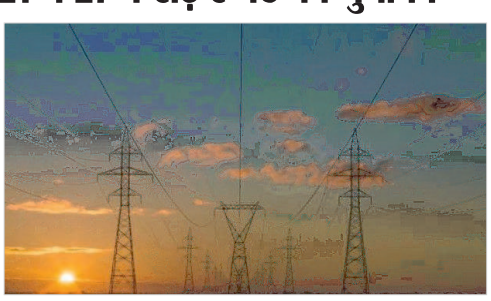

कला, हस्तशिल्प परियोजनाओं को मदद देगी ओएनजीसी

नई दिल्ली:

ओएनजीसी की अगुवाई में सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियां देश में विभिन्न कलाओं और शिल्प को प्रोत्साहन के लिए 75 परियोजनाओं की मदद करेगी। इसका मकसद इसके जरिए स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों को प्रोत्साहन देना है। देश की स्वतंत्रता के 75 साल के अवसर पर सरकार के आजादी के अमृत महोत्सव की तर्ज पर पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर ने ओएनजीसी की विभिन्न शिल्प और कला परियोनाओं को प्रोत्साहन देने की पहल का उद्घाटन किया। उन्होंने मध्य प्रदेश में ओएनजीसी के समर्थन वाली बांस कारीगरी परियोजना का भी शुभारंभ किया। कंपनी ने बयान में कहा, ''एक बड़ी पहल के तहत पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत आने वाले केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम देश के विभिन्न जिलों में 75 परियोजनाओं को समर्थन देंगे। ओएनजीसी ने देश में संघर्ष कर रही हस्तशिल्प परियोजनाओं के पुनरुद्धार और स्थानीय कारीगरों को सशक्त करने की पहल शुरू की है। इन 75 में से 15 परियोजनाओं को ओएनजीसी समर्थन देगी। मध्य प्रदेश की बांस हस्तशिल्प परियोजना 11 जून को शुरू हुई है।

बयान में कहा गया है कि शुरुआत में ओएनजीसी स्थानीय एनजीओ और मंचों के साथ देशभर में हस्तशिल्प क्षेत्र की 5 परियोजनाओं को समर्थन देगी। इन परियोजनाओं में वह 1.3 करोड़ रुपए खर्च करेगी।

फेम दो के तहत सब्सिडी में वृद्धि से बढ़ेगी इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग: हीरो इलेक्ट्रिक

नई दिल्ली:

इलेक्ट्रिक दोपहिया कंपनी हीरो इलेक्ट्रिक ने कहा है कि फेम दो के तहत सब्सिडी में बढ़ोतरी से देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ाने में मदद मिलेगी। हीरो इलेक्ट्रिक के प्रबंध निदेशक नवीन मुंजाल ने कहा, ''यह पिछले एक दशक में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कदम है। फेम दो के तहत सब्सिडी में बढ़ोतरी से देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का नया दौर शुरू होगा। सब्सिडी की सीमा में बढ़ोतरी पासा पलटने वाली होगी। इससे पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर पर पहुंचने के बीच उपभोक्ताओं का रुझान इलेक्ट्रिक स्कूटरों की ओर बढ़ेगा। सरकार ने शुक्रवार को फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्रिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वेहिकल्स इन इंडिया चरण दो (फेम इंडिया दो) योजना में आंशिक संशोधन किया है। इसके तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया के लिए मांग प्रोत्साहन को बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति केडब्ल्यूएच कर दिया गया है। पहले सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 10,000 प्रति केडब्ल्यूएच की समान सब्सिडी थी। इनमें प्लग इन हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड शामिल हैं।

बसें इसमें शामिल नहीं हैं। ताजा संशोधन के तहत भारी उद्योग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक दोपहिया के लिए प्रोत्साहन की सीमा को वाहन की लागत के 40 प्रतिशत तक सीमित किया है। पहले यह सीमा 20 प्रतिशत थी। मुंजाल ने कहा, ''हम अपनी पहुंच का विस्तार कर रहे हैं, चार्जिंग पॉइंट लगा रहे हैं और मेकेनिक्स को नए सिरे से प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया जा सके। उन्होंने कहा कि इन सबके बीच एक अनुकूल नीति से इलेक्ट्रिक वाहनों की वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा और क्षेत्र में बदलाव आएगा।

अश्विन से नहीं, अपने प्रयासों से ईजाद की कैरम बॉल : गौतम

नई दिल्ली । कृष्णप्पा गौतम को क्रिकेट के उनके शुरुआती दिनों में टीम के साथी खिलाड़ी 'भज्जी' (हरभजन सिंह का उपनाम) कह कर बुलाते थे, लेकिन इस ऑलराउंडर ने जिस तरह 'कैरम बॉल' ईजाद की है, उसमें उनकी गेंदबाजी में रविचंद्रन अश्विन का प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है। गौतम उन छह नए खिलाड़ियों में से एक हैं, जिन्हें श्रीलंका के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज के दौरे के लिए चुना गया है। इस दौरे पर 13 जुलाई से 25 जुलाई के बीच भारतीय टीम को तीन वनडे और इतने ही टी-20 मैचों की सीरीज खेलनी है। फर्स्ट क्लास में 166, लिस्ट ए में 70 और टी-20 में 42 विकेट लेने वाले इस खिलाड़ी से जब पूछ गया कि क्या उन्होंने अश्विन को देखकर 'कैरम बॉल' करना सीखा है, तो उन्होंने बताया कि इसे मैंने अपने प्रयासों से विकसित किया है। उन्होंने कहा कि यदि आपको शीर्ष स्तर पर खेलना है, तो आपको अपने दम पर कौशल विकसित करने की जरूरत होती है। बचपन में, मुझे ईरापल्ली प्रसन्ना सर ने भी कोचिंग दी है। उन्होंने कहा मुझे अश्विन की मानसिकता और खेल के प्रति दृष्टिकोण पसंद है। गौतम से जब भारतीय टीम में चयन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा आप सालों से जो सपना देखते है, जब वह सच होता है तब खुशी होती है।

जोकोविच से हारे नडाल

फ्रेंच ओपन के 108 मैचों में मिली तीसरी

पेरिस :

सर्बियाई स्टार नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंडस्लैम के चार से ज्यादा घंटे तक चले सेमीफाइनल में 'लाल बजरी के बादशाह' राफेल नडाल को शिकस्त दी और अब रविवार को फाइनल में उनका सामना यूनान के 22 वर्षीय स्टेफानोस सिटसिपास से होगा। रोलां गैरां में दोनों के बीच यह मुकाबला शानदार रहा जिसमें जोकोविच ने पहला सेट गंवाने के बाद वापसी की और नडाल की 14वें फ्रेंच ओपन और रिकार्ड 21वें ग्रैंडस्लैम खिताब की उम्मीद तोड़ दी। नडाल को लाल बजरी पर हराना किसी के लिए आसान नहीं है और इतिहास में केवल दो ही खिलाड़ी हैं जो ऐसा कर पाये हैं जिसमें जोकोविच ऐसा दो बार कर चुके हैं। जोकोविच ने शुक्रवार रात को दोनों के बीच करियर की 58वीं भिड़ंत में 3-6, 6-3, 7-6 (4), 6-2 से जीत दर्ज की। शीर्ष वरीय जोकोविच पहला सेट गंवाने के बाद चौथे सेट में 0-2 से पिछड़ रहे थे लेकिन फिर उन्होंने छह गेम जीतकर क्ले कोर्ट मेजर टूर्नामेंट में छठी बार फाइनल में प्रवेश किया। उन्होंने मैच के बाद कहा कि यह उन रात और मैचों में से एक है जो आपको हमेशा याद रहेंगे। निश्चित रूप से रोलां गैरां में मेरे मैचों में सर्वश्रेष्ठ मैच था और मैंने अपने पूरे करियर में जो मैच खेले हैं, उसमें टेनिस के स्तर को देखते हुए, कोर्ट (क्ले कोर्ट) में सफलता हासिल करने वाले मेरे सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी जिसका पिछले 15 से ज्यादा वर्षों से इस पर दबदबा रहा हो, इसे देखते हुए यह शीर्ष तीन मैचों में से एक था और माहौल अद्भुत था। नडाल की फ्रेंच ओपन के 108 मैचों में यह तीसरी हार थी और पिछले चार वर्षों से उन्होंने सभी मैच जीते थे जिसमें 2020 फाइनल में जोकोविच को हराना भी शामिल है। नडाल को फ्रेंच ओपन में पहली हार 2009 में रोबिन सोडरलिंग के हाथों मिली थी और फिर जोकोविच ने उन्हें 2015 में हराया था। 34 वर्षीय जोकोविच ने कहा कि जब भी आप कोर्ट पर उससे खेलने के लिये उतरते हो तो आप जानते हो कि आपको इस खिलाड़ी के खिलाफ जीत हासिल करने के लिये 'माउंट एवरेस्ट' पर चढ़ने जितनी मशक्कत करनी होगी। अब जोकोविच रविवार को दूसरी बार फ्रेंच ओपन खिताब और ओवरऑल 19वीं मेजर चैम्पियनशिप हासिल करने के लिएसिटसिपास के सामने होंगे जिन्होंने छठे वरीय एलेक्जेंडर ज्वेरेव को 6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया और वह ऐसा करने वाले यूनान के पहले खिलाड़ी बने। जोकोविच अभी नडाल और रोजर फेडरर (दोनों के 20 ग्रैंडस्लैम खिताब) से दो खिताब पीछे हैं और वह इस अंतर को कम करना चाहेंगे। नडाल ने मैच के बाद स्वीकार किया कि टाईब्रेकर के तीसरे सेट में उनके खराब खेल का कारण थकान हो सकता है जिसमें उन्होंने एक डबल फाल्ट की। गलतियां हो सकती हैं लेकिन अगर आप जीतना चाहते हो तो आप ऐसी गलतियां नहीं कर सकते। यही टेनिस है। जो परिस्थितियों के अनुरूप बेहतर ढंग से खेल पाया, वह जीत का हकदार है। इसमें कोई शक नहीं, वह जीत का हकदार था। यह सेट एक घंटे 33 मिनट तक चला।

यूरो 2020 से बड़ी खेल प्रतियोगिताओं की वापसी हुई

रोम ।

कोरोना वायरस महामारी के कारण पिछले साल खेल गतिविधियों के प्रभावित होने के बाद बाद रोम के स्टाडियो ओलंपिको में महामारी के दौर के सबसे बड़े खेल आयोजनों में से एक यूरो 2020 फुटबॉल चैम्पियनशिप शुक्रवार को शुरू हुई। एक साल की देरी से हो रहे इस टूर्नामेंट का पहला मैच उसी देश में खेला गया जो एशिया के बाहर कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था और जिसने सबसे पहले पूरे देश में लॉकडाउन लगाया था। इटली ने घरेलू मैदान पर टूर्नामेंट के पहले मैच में तुर्की को 3-0 से हराकर टूर्नामेंट में शानदार आगाज किया। कोरोना वायरस से यूरोप में 10 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई जिसमें इटली में ही मृतकों की सख्या 1.27 लाख से ज्यादा है। रोम में मैच देखने आये प्रशंसकों को स्टेडियम में आने के लिए वायरस के खिलाफ टीका लेने के प्रमाण के साथ कोविड-19 जांच की नेगेटिव रिपोर्ट को दिखाना जरुरी था। यूरो 2020 का आयोजन अगर सफल तरीके से हुआ तो इससे तोक्यो ओलंपिक के आयोजकों का हौसला भी बढ़ेगा, जिसे पिछले साल एक साल के लिए स्थगित कर दिया गया था। तोक्यो 2020 का आगाज 23 जुलाई से होगा। 15 महीने पहले पूर्ण लॉकडाउन में जाने के बाद से

इटली के उद्घाटन मैच ने देश में सबसे बड़ी संख्या में दर्शक एक साथ जमा हुए। स्टेडियम में हालांकि क्षमता के 25 प्रतिशत ही दर्शक थे। रोम के निवासी फेड्रिको रिवा में कहा कि यह बहुत भावनात्मक पल है, बहुत शानदार पल। यह माहौल ऐसा जो हम सभी याद रहेगा। प्रशंसकों से भरा स्टेडियम, हमें इस सब की जरूरत थी, हमें वास्तव में इसकी जरूरत थी।

ताइक्वांडो खिलाड़ी अरुणा को वाइल्ड कार्ड से टोक्यो पैरालिंपिक में मिली एंट्री, भावुक हुए पिता

नई दिल्ली। भारतीय ताइक्वांडो खिलाड़ी अरुणा तंवर को टोक्यो पैरालिंपिक में वाइल्ड कार्ड के जरिए एंट्री मिल गई है। वह इसमें भाग लेने वाली पहली भारतीय ताइक्वांडो खिलाड़ी बन जाएंगी। बेटी सफलता पर पिता बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि सरकार अरुणा का साथ देगी और उसके सपनों को पूरा करने में मदद करेगी। बेटी सफलता से गदगद अरुणा के पिता ने बताया कि अब तक का सफर अरुणा का गहने बेचकर और उधार पैसों से पूरा हुआ है। उन्होंने कहा कोच और उसकी मेहनत रंग लाई। हमने बहुत सारी आर्थिक तंगी का सामना किया है, लेकिन किसी तरह मैंने गहने बेचकर या पैसे उधार लेकर उसके खर्चों का प्रबंधन किया। मैं सरकार से हमारी मदद करने और उसके बारे में सोचने का आग्रह करता हूं। अरुणा इस समय महिलाओं की अंडर 49 श्रेणी में दुनिया की चौथे नंबर की खिलाड़ी हैं। पांच बार की राष्ट्रीय चैम्पियन अरुणा पिछले चार साल में एशियाई पैरा ताइक्वांडो चैम्पियनशिप और विश्व पैरा ताइक्वांडो चैम्पियनशिप में पदक जीत चुकी हैं। टोक्यो पैरालिंपिक 24 अगस्त से पांच सितंबर तक खेले जाएंगे। दूसरी ओर, अरुणा तंवर ने मार्शल आर्ट को अपना पैशन बताते हुए कहा मैं बचपन से मार्शल आर्ट की बहुत बड़ी प्रशंसक रही हूं। पहले मैं सामान्य वर्ग में खेलती थी, लेकिन मुझे वहां ज्यादा सफलता नहीं मिल रही थी। मुझे पैरा-ताइक्वांडो के बारे में पता चला और इसे खेलना शुरू कर दिया। वह कहती हैं- मेरे माता-पिता ने मेरा साथ दिया। वे हर राष्ट्रीय टूर्नामेंट में मेरे साथ थे। मां और पिता दोनों ने मुझ पर विश्वास किया और मैंने अब तक जो कुछ भी हासिल किया है, वह उन्हीं की वजह से है। पैरालिंपिक में पदक जीतने और उन्हें गौरवान्वित करने की कोशिश करूंगी।

खेलमंत्री ने ओलंपिक और उसके बाद के एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए एथलीट चोट प्रबंधन प्रणाली लॉन्च की

नई दिल्ली।

खेलमंत्री किरेन रिजिजू ने केंद्रीय एथलीट चोट प्रबंधन प्रणाली (सीएआईएमएस) का शुभारंभ किया। यह युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा एथलीटों को दी जाने वाली स्पोर्ट्स मेडिसिन और स्वास्थ्यलाभ सहायता को सुव्यवस्थित करने के लिए अपनी तरह की पहली पहल है। सीएआईएमएस की कोर कमेटी में डॉ. एसकेएस मरिया, डॉ. दिनशॉ पारदीवाला, डॉ. बी वी श्रीनिवास और श्रीकांत अयंगर जैसे प्रख्यात शीर्ष विशेषज्ञ शामिल हैं। सीएआईएमएस का उद्देश्य एथलीट की खेल मैदान (भौगोलिक स्थिति) के निकटत उत्तम खेल चोट प्रबंधन सहायता प्रदान करना है। सीएआईएमएस देश भर के एथलीटों के लिए उपयुक्त चोट उपचार प्रोटोकॉल को एक समान बनाने में मदद करेगा। यह योजना उन एथलीटों की मदद के साथ शुरू होगी जो टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना (टॉप्स) विकास समूह का हिस्सा हैं, जिनके ओलंपिक 2024 और उसके बाद भाग लेने की उम्मीद है। रिजिजू ने सीएआईएमएस शुरू करने की पहल की सराहना की। उन्होंने कहा, यह लंबे समय से हर किसी की इच्छा थी कि हमारे देश में एक केंद्रीकृत एथलीट चोट प्रबंधन प्रणाली हो। मैंने कभी-कभी देखा है कि सामान्य चोटों के लिए भी समय पर इलाज नहीं मिल पता है जिससे एथलीट का करियर प्रभावित होता है। आज यह एक बहुत ही सादगीपूर्ण शुरुआत है, लेकिन यह हमें एक ऐसी प्रणाली की ओर ले जाएगी जहां हमारे पास एथलीट की चोट से निपटने के लिए प्रबंधन का एक बहुत ही पेशेवर तरीका होगा। इस पहल के महत्व के बारे में बताते हुए सचिव (खेल) रवि मित्तल ने कहा, खेल बहुत प्रतिस्पर्धी हो गया है और जब हमारे एथलीट पदक जीतने के लिए अपना पूरा जोर लगाते हैं तो वे कभी-कभी घायल हो जाते हैं। इन चोटों का सही समय पर और सही तरीके से इलाज करना अनिवार्य है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारे एथलीट पूरी तरह स्वास्थ्य और फॉर्म में हैं। सीएआईएमएस से एथलीट की चोटों के प्रबंधन और इलाज के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव की उम्मीद है। इसमें निम्नलिखित चार संरचनाएं होंगीः एथलीट वेलनेस सेल, ऑन-फील्ड स्पोर्ट्स मेडिसिन विशेषज्ञ, राष्ट्रीय संसाधन रेफरल टीम और एक केंद्रीय कोर टीम। डॉ. एसकेएस मरिया, सेंट्रल कोर टीम के अध्यक्ष ने सीएआईएमएस की सराहना की और कहा कि यह एथलीट चोटों के इलाज में भौगोलिक बाधाओं को दूर करने की दिशा में एक लंबा सफर तय करेगा।

संक्षिप्त समाचार

भारत की सीमित ओवरों की टीम मुंबई में 14 दिन के पृथकवास में रहेगी

नई दिल्ली । शिखर धवन की अगुआई वाली भारत की सफेद गेंद की टीम मुंबई में 14 से 28 जून तक पृथकवास में रहेगी और श्रीलंका के खिलाफ 13 जुलाई से शुरू होने वाली छह मैचों की श्रृंखला के लिए कोलंबो रवाना होने से पहले खिलाड़ियों के एक दिन छोड़कर छह आरटी-पीसीआर परीक्षण होंगे। श्रीलंका जाने वाली टीम के लिए सभी मानक परिचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) समान होंगी जैसे इंग्लैंड के खिलाफ विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल और पांच मैचों की श्रृंखला के लिये ब्रिटेन में मौजूद भारत की टेस्ट टीम के लिए अपनाई गई थीं। इसकी जानकारी रखने वाले भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के सूत्र ने गोपनीयता की शर्त पर कहा कि सभी नियम वैसे ही होंगे जैसे इंग्लैंड रवाना होने के लिये अपनाये गये थे। बाहर के राज्यों से आने वाले खिलाड़ी चार्टर फ्लाइट से आयेंगे और कुछ कर्मिशियल एयरलाइन की बिजनेस क्लास से यात्रा करेंगे। वे सात दिन तक अपने ही कमरे में पृथकवास करेंगे और फिर जैविक रूप से सुरक्षित वातावरण में कॉमन स्थान पर मिल सकेंगे। खिलाड़ी अलग अलग समय पर जिम सत्र में हिस्सा ले सकेंगे। तीन मैचों की वनडे श्रृंखला 13 जुलाई से शुरू हो रही है तो उम्मीद है कि भारतीय टीम को व्यक्तिगत ट्रेनिंग सत्र के बाद मैच की परिस्थितियों का अभ्यास कराया जाएगा। इससे पहले उन्हें कोलंबो में टीम होटल में तीन दिन तक कमरे में अलग रहना होगा। सूत्र ने कहा कि यह उसी तरह होगा जैसा इंग्लैंड में हो रहा है। मैच की तरह की परिस्थितियां बनाई जाएंगी और टीम के अंदर ही अभ्यास कराया जाएगा। आप अपने मुख्य खिलाड़ियों को पहली ही गेंद पर आउट नहीं होने देना चाहते। हर किसी को ट्रेनिंग की जरूरत है तो ये अभ्यास मैच नहीं होंगे। भारतीय टीम वर्षों से कोलंबो में हमेशा ताज समुद्र होटल में रूकती रही है।

ऐतिहासिक खिताबी मुकाबला से पहले ऋषभ पंत ने दिखाया दमदार फॉर्म

नई दिल्ली । विराट कोहली की कप्तानी में टीम इस समय इंग्लैंड दौरे पर है। जहां न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ऐतिहासिक खिताबी मुकाबला खेलने के बाद में मेजबान के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। 18 से 22 जून तक न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले फाइनल से पहले भारतीय बल्ले लेबाज ऋषभ पंत ने अपनी फॉर्म दिखा दी। उन्होंने भारत के इंट्रा स्क्वॉड अभ्यास मैच में शानदार अर्धशतक जड़ दिया। ऐतिहासिक फाइनल से पहले भारतीय टीम ने शुक्रवार से इंट्रा-स्क्वाड मैच खेलना शुरू किया था। इसके दूसरे दिन पंत ने बेहतरीन पारी खेलकर अपनी तैयारियों को जायजा लिया। इस अभ्यास मैच में रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, रवींद्र जडेजा जैसे बल्लेबाज एक टीम में हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, इशांत शर्मा, आर अश्विन जैसे मुख्य गेंदबाज दूसरी टीम में हैं। टीम इंडिया बिना किसी मैच प्रैक्टिस के फाइनल में उतरेगी।

आईडब्ल्यूएफ ने मीराबाई चानू के तोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने की पुष्टि की

नयी दिल्ली,

अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ (आईडब्ल्यूएफ) ने शनिवार को भारत की अनुभवी भारोत्तोलक मीराबाई चानू के महिलाओं के 49 किग्रा वर्ग में तोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने की पुष्टि कर दी। भारोत्तोलन में 2017 विश्व चैंपियन चानू ने अप्रैल में ताशकंद में एशियाई चैम्पियनशिप में क्लीन एंव जर्क में विश्व रिकॉर्ड के साथ कांस्य पदक जीतकर तोक्यो में अपना स्थान सुरक्षित किया था, जिसकी अब आधिकारिक पुष्टि हो गयी।मणिपुर की इस 26 साल की खिलाड़ी ने आईडब्ल्यूएफ की रैंकिंग सूची के आधार पर कोटा हासिल किया। यह भारतीय भारोत्तोलक 49 किग्रा वर्ग में 4133,6172 अंक के साथ दूसरे स्थान पर काबिज है। भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) ने उन्हें टैग करते हुए ट्वीट किया, ''टॉप्स एथलीट भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने आईडब्ल्यूएफनेट रैंकिंग में 49 किग्रा भार वर्ग में दूसरे स्थान पर आने के बाद तोक्यो 2020 का क्वालीफिकेशन हासिल किया।''चानू रैंकिंग में पहले चौथे स्थान पर थी लेकिन उत्तर कोरिया के ओलंपिक से हटने से वह दूसरे स्थान पर पहुंच गयी। रियो में निराशाजनक प्रदर्शन के पांच साल बाद ओलंपिक में चानू की यह

दूसरी उपस्थिति होगी। रियो ओलंपिक 2016 में वह क्लीन एंव जर्क में किसी भी भार को उठाने में विफल रही और प्रतियोगिता से बाहर हो गयी थी। पुरुषों के 67 किग्रा वर्ग में, भारत के जेरेमी लालरिननुंगा 12वें स्थान पर हैं और कोरिया के हाक मायोंगमोक से महाद्वीपीय कोटा में पिछड़ गये। भारत के इस 18 साल के खिलाड़ी के पास अभी भी क्वालीफाई करने का मौका है। इसकी आखिरी सूची 25 जून को जारी होगी।

अमेरिका की लीग ने 80 फर्स्ट क्लास खिलाड़ियों को किया साइन, यह बड़े नाम भी हैं शामिल

न्यूयॉर्क ।

अमेरिकन क्रिकेट एंटरप्राइजेज (एसीई) ने माइनर लीग क्रिकेट (एमआईएलसी) टी-20 की सभी 27 फ्रेंचाइजियों के लिए टीम ड्राफ्ट की घोषणा कर दी है। आगामी 31 जुलाई से शुरू हो रहे इस टी-20 टूर्नामेंट के लिए दुनिया भर के 80 से अधिक प्रथम श्रेणी क्रिकेटरों को साइन किया गया है। सप्ताहांत में खेले जाने और छह हफ्ते तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में दुनिया भर के 80 से अधिक प्रथम श्रेणी खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिनमें से कई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी खेल चुके हैं। खिलाड़ियों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि 12 खिलाड़ी अभी भी अपना अमेरिकी वीजा मिलने का इंतजार कर रहे हैं। माइनर लीग क्रिकेट टी-20 टूर्नामेंट कुछ परिचित अंतरराष्ट्रीय नामों को पेश करने के लिए तैयार है। न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर कोरी एंडरसन को उनकी घरेलू फ्रेंचाइजी डलास ने साइन किया है, जबकि पूर्व दक्षिण अफ्रीकाई ऑफ स्पिनर डेन पीड्ट को डीसी हॉक्स ने चुना है। वहीं वेस्ट इंडीज के स्पिनर रहकीम कॉर्नवाल अटलांटा फायर के लिए उतरेंगे और पाकिस्तानी जोड़ी शमी असलम और हम्माद आजम गोल्डन स्टेट ग्रिजलीज फ्रेंचाइजी का प्रतिनिधित्व करेंगे। माइनर लीग टूर्नामेंट के अंतिम ड्राफ्ट ने रिकाडर पॉवेल के रूप में भी एक सरप्राइज दिया है, जो 42 साल की उम्र में अटलांटा परमवीर्स के लिए लीग क्रिकेट में वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। माइनर लीग क्रिकेट ने इस साल प्रथम श्रेणी के कुछ भारतीय प्रतिभाओं को भी मौका दिया है। भारतीय अंडर-19 टीम के पूर्व और बारबाडोस ट्राइडेंट्स के मौजूदा विकेटकीपर बल्लेबाज स्मित पटेल को मैनहट्टन वॉरर्स ने अनुबंधित किया है। पटेल 55 प्रथम श्रेणी मैच खेलने और अपने भारतीय क्रिकेट करियर को अलविदा कहने के बाद अब अमेरिका में रहते हैं।

मैच के दौरान गेंद घायल हुए आंद्रे रसेल, स्ट्रेचर से बाहर ले जाना पड़ा

नई दिल्ली । वेस्टइंडीज के धाकड़ ऑलराउंडर आंद्रे रसेल पाकिस्तान सुपर लीग में खेलते हुए घायल हो गए। रसेल शुक्रवार को पीएसएल में अपना पहला मैच खेल रहे थे। क्वेटा ग्लेडिएटर्स के बल्लेबाज रसेल को इस्लामाबाद यूनाइटेड के गेंदबाज मोहम्मद मूसा की गेंद सिर पर लगी। सिर पर गेंद लगने से रसेल कन्कशन के शिकार हो गए। हादसा क्वेटा के पारी के 14वें ओवर में हुआ। रसेल ने मूसा के इस ओवर में लगातार दो छक्के लगाए। लेकिन वह मूसा की अगली गेंद, जो बाउंसर थी उसे पढ़ नहीं पाए, गेंद उनके हेलमेट पर लगी। सिर पर गेंद लगते ही फिजियो रसेल को चैक करने मैदान पर आए। रसेल ने इसके बाद बल्लेबाजी जारी रखी, लेकिन अगली ही गेंद पर आउट हो गए। रसेल स्ट्रेचर से मैदान के बाहर ले जाकर उन्हें बाद में अस्पताल ले जाया गया। रसेल फील्डिंग के दौरान भी मैदान पर नहीं उतरे। उनकी जगह नसीम शाह ने ली। नसीम को रसेल की जगह लिए जाने का फैसला इस्लामाबाद टीम को पसंद नहीं आया। कप्तान शादाब खान ने अपनी टीम की बैटिंग शुरू होने से पहले अंपायर अलीम दार से बात भी की। बता दें कि लाइक-टू-लाइक रिप्लेसमेंट का फैसला मैच रेफरी करता है।

सुनील छेत्री ने कहा- जब भी निराश होता हूं तो मेस्सी का वीडियो देखता हूं

दोहा ।

फुटबॉल मैदान पर लियोनेल मेस्सी के मंत्रमुग्ध कर देने वाले खेल को देख कर सुनील छेत्री को निराशा के समय भी खुशी मिलती है लेकिन भारत के इस करिश्माई फुटबॉल खिलाड़ी ने शनिवार को यह साफ कर दिया कि अर्जेंटीना के इस दिग्गज खिलाड़ी के साथ उसकी तुलना 'बेवकूफी' की तरह है। मौजूदा सक्रिय खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय गोल करने के मामले में छेत्री ने मेस्सी को पछाड़ दिया है और दूसरे स्थान पर आ गए है। छेत्री ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर के 16 साल पूरे होने पर एआईएफएफ (अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ) को दिए साक्षात्कार में कहा कि जब मैं दुखी होता हूं तो मैं मेस्सी के वीडियो देखता हूं और इससे मुझे खुशी मिलती है। इसलिए जब मैं उनसे मिलूंगा, तो मैं उनसे कहूंगा कि मैं उनका प्रशंसक हूं और उनसे अच्छे से हाथ मिलाउंगा। छेत्री से जब पूछा गया कि मेस्सी से मिलने पर वह क्या करेंगे तो उन्होंने कहा कि उनके 'हाय (अभिवादन)' करने के बाद कहूंगा कि मैं सुनील छेत्री हूं और मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। मैं उन्हें परेशान नहीं करूंगा। अगर मैं उससे मिलूं तो मुझे खुशी होगी, अगर मैं नहीं हूं, तो भी मैं अच्छा ही महसूस करूंगा। छेत्री ने फीफा विश्व कप 2022 एवं एशियाई कप 2023 की संयुक्त क्वालीफाइंग मैच में सात जून को बांग्लादेश के खिलाफ दो गोल कर मेस्सी को पीछे छोड़ा। भारत ने इस मैच कों 2-0 से जीता था। छेत्री के नाम 74 अंतरराष्ट्रीय गोल है तो वही मेस्सी ने अंतरराष्ट्रीय मैचों में 72 गोल किए है। उन्होंने कहा कि दुनिया में किसी अन्य की तरह मैं भी मेस्सी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। हम दोनों में कोई तुलना ही नहीं है। मैं बस खुश हूं कि मुझे अपने देश के लिए गोल करने का मौका मिला और मैं गर्व महसूस कर रहा हूं। भारतीय कप्तान ने कहा कि मैं उन सभी महान खिलाड़ियों के साथ अपनी तुलना करने की बेवकूफी नहीं करना चाहता। ऐसे हजारों खिलाड़ी हैं जो मुझसे बेहतर हैं और ये सभी लियोनेल मेस्सी के प्रशंसक भी हैं। यही अंतर है। छेत्री ने आज ही के दिन 16 साल पहले पाकिस्तान के खिलाफ क्वेटा में अंतरराष्ट्रीय पदार्पण किया था। उस समय टीम के मुख्य कोच सुखविंदर सिंह थे।

शाकिब अल हसन पर लगा एक बार फिर बैन, इतने मैचों के लिए हुए निलंबित : रिपोर्ट

ढाका । बांग्लादेश के स्टार क्रिकेटर शाकिब अल हसन को मोहम्मडन स्पोर्टिंग और अबाहानी लिमिटेड के बीच मैच के दौरान मैदानी विवाद के कारण ढाका टी20 प्रीमियर लीग के चार मैचों से निलंबित कर दिया गया है। बांग्लादेश के प्रमुख क्रिकेट पोर्टल के अनुसार कि मोहम्मडन स्पोर्टिंग के कप्तान शाकिब अल हसन पर ढाका प्रीमियर लीग के दौरान उनकी तुनकमिजाजी के कारण चार मैचों का प्रतिबंध लगा दिया गया है। वह डीपीएल के आठवें, नौवें, दसवें और 11वें दौर के मैच नहीं खेल सकेंगे। मोहम्मडन ने पहला मैच डकवर्थ लुईस प्रणाली से जीत लिया था लेकिन शाकिब ने दो बार उसमें आपा खोया। एक बार बांग्लादेश के अपने साथी खिलाड़ी मुशफिकुर रहीम के खिलाफ पगबाधा की पुरजोर अपील खारिज किए जाने पर उन्होंने स्टम्प पर लात मार दी। दूसरी बार अबाहानी की पारी के न्यूनतम छह ओवर पूरे होने में जब एक गेंद बाकी थी तो अंपायर ने कवर्स बुला लिए जिस पर वह मिडआफ से भागे और स्टम्प उखाड़ दिया। मैच बहाल हुआ और शाकिब की टीम आराम से जीत गई लेकिन उन्होंने विरोधी टीम के अधिकारियों और बांग्लादेश के पूर्व कप्तान खालिद महमूद सुजोन के साथ बदसलूकी की। बाद में उन्होंने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर माफी भी मांगी लेकिन निलंबन से नहीं बच सके। पोर्टल ने बताया कि ढाका मेट्रोपोलिस क्रिकेट समिति ने यह फैसला लिया जिसके अध्यक्ष काजी इमाम हैं। शाकिब की यह हरकत सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गई और स्टम्प उखाड़ते हुए उनकी वीडियो फुटेज को लाखों लोगों ने साझा किया।

सूरत में कर्जे में डूबा हुआ व्यापारी शराब के धंधे की तरफ मुड़ गया

पुलिस को कहा कि कोरोना में धंधा ठप होने पर आर्थिक रूप से नुकसान हो जाने से कर्जा की भरपाई करने के लिए व्यापार शुरू किया

सूरत।

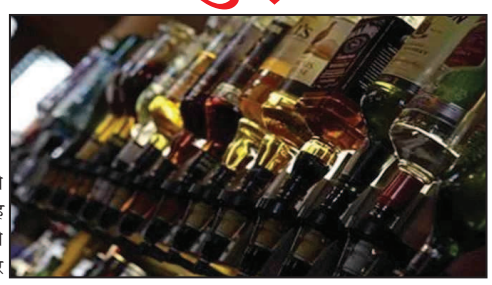

सूरत में कोरोना काल में ही जिस तरीके से लोगों के व्यापार -धंधे बंद हो गये है या बेकार बनने के बाद परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो गया है ऐसे में परिवार का आर्थिक गुजारा चलाने के लिए लोग गलत काम कर रहे है तब कोरोना को लेकर बेकार हुए कई युवक शराब की खेप लगाते हुए पहले भी गिरफ्तार हो चुके है। अब और एक व्यापारी की इस अपराध में गिरफ्तार किया गया है। सूरत के डिंडोली क्षेत्र में स्थित श्यामविला सोसाइटी में रहते मुकेशकुमार राधेश्याम सामरा ऐसे तो साड़ी का व्यापारी लेकिन पिछले डेढ़ वर्ष में कोरोना काल में लॉकडाउन को लेकर इसका धंधा ठप हो गया और उनके ऊपर कर्जा हो गया। जिसकी वजह से आर्थिक तंगी से बाहर आने के लिए उसने शराब का व्यापार शुरू किया था। हालांकि, अपनी गाड़ी में शराब का जत्था अपनी सोसाइटी में पार्किंग रहे गाड़ी में छिपाया था हालांकि इस मामले में पुलिस को खबर मिलने पर पुलिस ने यह व्यापारी को गिरफ्तार करके इसकी पूछताछ शुरू करके व्यापारी ने खुद शराब का व्यापार करते होने का कबूला। पुलिस ने २,७७ लाख का मालसामान के साथ इसके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की। हालांकि यह व्यापारी को शराब देने वाला आयुस नाम के बुटलेगर को पुलिस ने वांटेड घोषित करके इसे गिरफ्तार करने के लिए खोजबीन शुरू कर दी है। इसके पहले केस ऐसा नहीं है व्यापारी आर्थिक परिस्थिति बिगड़ने पर उसने शराब का व्यापार करना पड़ा पहले में कई कपड़े के व्यापारी इसी अनुसार शराब का व्यापार के साथ जुड़े हो और पुलिस के द्वारा गिरफ्तार हुआ है।

युवक का टेस्ट एक में पॉजिटिव आया और एक में निगेटिव

सूरत।

सूरत में कोरोना रिपोर्ट को लेकर निजी लैब की गलती सामने आई है। एक ही दिन में एक लैब में पॉजिटिव तो दूसरी लैब में निगेटिव रिपोर्ट आने पर वराछा का रत्नकलाकार दुविधा में पड़ गया। सूरत में कोरोना के बाद सभी रत्नकलाकारों को काम पर बैठने के पहले रैपिड टेस्ट अनिवार्य है।

सभी रत्नकलाकारों को यह रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही काम पर रखा जाता है। अब सूरत के वराछा क्षेत्र में रहते चिंतन भाई अकबरी अपना कोरोना एंटिजन रैपिड टेस्ट कराने के लिए योगीचौक के स्वस्तिक प्लाजा के एक्युरेट लैब में एंटिजन रैपिड टेस्ट कराने के लिए पहुंचे थे। जहां रिपोर्ट कराने पर उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर वह परेशान हो गये। क्योंकि उनको कोरोना का कोई लक्षण नहीं था।

वह सिर्फ हीरा के कारखाने में काम करने के लिए रिपोर्ट निकालने के लिए गये थे। रिपोर्ट मामले में आशंका होने पर उन्होंने सरथाणा में स्थित एचसीएल लैब में रिपोर्ट करने के लिए गये थे। जहां उनका एंटिजन रैपिड टेस्ट निगेटिव आया। दोनों जगह पर होकर उन्होंने रिपोर्ट के ६०० रुपये चुकाये।

हालांकि एक ही दिन में एक लैब में पॉजटिव तो दूसरी लैब में निगेटिव रिपोर्ट आने पर वराछा का रत्नकलाकार दुविधा में पड़ गया।

अहमदाबाद की ७० फीसदी आबादी में एंटीबॉडी विकसित हुई

अहमदाबाद।

अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा मई महीने के अंतिम सप्ताह में तथा जून की शुरूआत में किया गया एक पांच में सर्वेक्षण में जानने को मिला है कि, कोरोना की घातक दूसरी लहर के बाद अहमदाबाद में करीब ७० फीसदी आबादी में स्क्र- श्ट्रङ्क२ एंटिबॉडी विकसित हुई है। एएमसी द्वारा किए गए इस सर्वेक्षण में १५००० से ज्यादा अहमदाबादियों ने हिस्सा लिया। फरवरी, २०२१ में किया गया चौथा सीरो सर्वेक्षण में जानकारी मिली है कि शहर के सिर्फ २८ फीसदी लोगों की कोरोना के विरूद्ध एंटिबॉडी विकसित हुई है। जबकि जून, २०२० में पहला सीरो सर्वेक्षण किया गया तब जानकारी मिली कि सिर्फ १८ फीसदी लोगों में एंटिबॉडी विकसित हुई है। उल्लेखनीय है कि २५ अप्रैल, २०२१ को अहमदाबाद शहर में केस की संख्या बढ़कर ५७९० हो गई थी, जो पिछले वर्ष में दीपावली के बाद नवंबर दिसंबर में स्थित लहर की तुलना में १६ गुना ज्यादा है। विशेषज्ञों का कहना है कि, एंटीबॉडी ज्यादा प्रमाण में विकसित हुई है इसका अर्थ है कि डेल्टा वेरियंट क्ब६१७.२ के संक्रमण का खतरा ज्यादा है और अहमदाबाद में ज्यादातर केस में यह वेरियंट देखने को मिला। सीनियर स्टेट हेल्थ ऑफिसर बताते है कि, एएमसी द्वारा हाल में किया गया सर्वेक्षण के प्राथमिक परिणामों में जानने को मिला है कि अहमदाबाद की ७० फीसदी थी ज्यादा आबादी में वायरस के विरूद्ध एंटीबॉडी विकसित हुई है। एएमसी के हेल्थ विभाग के विशेषज्ञों द्वारा यह डेटा का ज्यादा विश्लेषण किया जाएगा। स्वास्थ्य अधिकारी आगे बताते है कि, कोरोना की दूसरी कोई लहर आये इसके खिलाफ लड़ने के लिए टीकाकरण और मास्क शहर के प्राथमिक हथियार होना चाहिए। डेल्टा वेरियंट का सामना करने के बाद अहमदाबादियों को अन्य कोई भी संभावना को हल्के में नहीं लेना चाहिए।

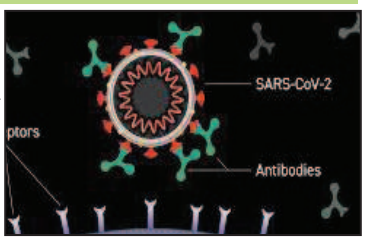

अंबाजी मंदिर में आते भक्त प्रसाद बिना नहीं जाएंगे

पालनपुर।

बनासकांठा के जिला कलेक्टर आनंद पटेल की अध्यक्षता में मंदिर ट्रस्ट द्वारा शुरू किए गए प्रॉजेक्ट के तहत अंबाजी मंदिर में दर्शन करने के लिए आते भक्तों को मुफ्त में भोजन मिलेगा। सदाव्रत प्रॉजेक्ट के तहत १४ जून से सैकड़ों भक्तों को मुफ्त में भोजन दिया जाएगा। अंबाजी यह माता जगदंबा का मंदिर है और यहां हर वर्ष माता के दर्शन करने के लिए हजारों भक्त आते है। अंबाजी मंदिर के ट्रस्ट ने सदाव्रत के लिए अंबिका भोजनालय की शुरूआत की थी। जिसका संचालन जलियाणा सदाव्रत द्वारा संचालित जय जलियाणा फाउंडेशन करता था। सदाव्रत का आयोजन तीन महीने के लिए किया गया है और यह बनासकांठा के कलेक्टर आनंद पटेल के निरीक्षण के तहत संचालित किया जाएगा, जो अंबाजी मंदिर में संचालन करते आरासुरी अंबाजी माता देवस्थान ट्रस्ट के पूर्व प्रभारी है। एएएमडीटी के प्रशासक एसजे चाडवा ने बताया कि, मंदिर हर वर्ष में करीब २० लाख भक्तों को भोजन देता था। लेकिन टोकन की कीमत पर। हालांकि, कई दाता आगे आये और मंदिर के ट्रस्ट की तरफ से मुफ्त में भोजन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा। पटेल ने फूड मैनेजमेंट यह दाताओं को सौंपने का निश्चय किया है, यह चावडा ने बताया। हम फ्री फूड प्रॉजेक्ट हमेशा के लिए रखना चाहते है। हालांकि हाल मंदिर का मैनेजमेंट प्रयोगात्मक आधार पर तीन महीने के लिए प्रॉजेक्ट को लेकर सहमत हुए हैं।

प्रॉजेक्ट को बरकरार रखने का निर्णय तीन महीने के बाद इसकी प्रगति की समीक्षा करने के बाद लिया जाएगा। अंबाजी मंदिर की बात करे तो, कोरोना महामारी की दूसरी लहर की वजह से वह पिछले दो महीने से बंद था। हालांकि, सरकार ने नियंत्रण में छूट देने पर दो महीने के बाद आज फिर से मंदिर के द्वार भक्तों के लिए खुले है। हालांकि, निर्धारित समय में मंदिर परिसर में ५० से ज्यादा भक्तों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मंदिर में आये भक्त सामाजिक दूरी का पालन करे इसके लिए उचित कदम उठाया जाएगा।

सीएम अरविंद केजरीवाल सोमवार को गुजरात आएंगे

१४ मई को केजरीवाल अहमदाबाद के नवरंगपुरा इलाके में मौजूद आप कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे

गांधीनगर।

२०२२ में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में शानदार जीत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी गुजरात में भी सियासी जमीन तलाश कर रही है। गुजरात के लोगों को बीजेपी-कांग्रेस के अलावा तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल गुजरात दौरे पर आने वाले हैं।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल गुजरात के एक दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी केजरीवाल के दौरे के बाद अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेगी। १४ मई को केजरीवाल अहमदाबाद के नवरंगपुरा इलाके में मौजूद आप कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। केजरीवाल सुबह १० .२० बजे अहमदाबाद पहुंचेंगे, इसके बाद दोपहर में वह वल्लभभवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। केजरीवाल की मौजूदगी में गुजरात के वरिष्ठ पत्रकार ईशुदान गढ़वी समेत कई नेता आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे। उसके बाद केजरीवाल शाम को दिल्ली लौट जाएंगे। आजादी के बाद पहली बार डायमंड सिटी सूरत नगर निगम में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है।

पहली बार गुजरात में प्रवेश करने वाली AAP २७ सीटों पर जीत हासिल कर शानदार राजनीतिक पारी का आगाज किया है। १२० सीटों वाली निगम में भाजपा ने ९३ सीटें जीतीं। जबकि कांग्रेस को पाटिदार अनामत आंदोलन समिति से झगड़ा करना महंगा पड़ा। अपमानजनक हार के बाद लोगों के बीच चर्चा चलने लगी है कि कांग्रेस को अब राजनीति से सन्यास ले लेना चाहिए।

भाई को छुड़ाने गए होमगार्ड ने थाने में हंगामा किया

अहमदाबाद।

अहमदाबाद शहर के कृष्णानगर इलाके से पुलिस ने नाइट कर्फ्यू के दौरान घूमने वाले लोगों को पकड़कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की थी। इस दौरान कर्फ्यू उल्लंघन में पकड़े गए युवक को छुड़ाने के लिए उसका होमगार्ड भाई वर्धी में थाने आया और जमकर हंगामा किया। इतना ही नहीं आरोपी का भाई पुलिस स्टेशन के कागजात को भी फाड़ दिया। कृष्णानगर पुलिस ने होमगार्ड के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है।

मिल रही जानकारी के अनुसार कृष्णानगर थाने के डी-स्टाफ पुलिसकर्मी रात में कर्फ्यू का पालन कराने के लिए गश्त कर रहे थे। इस बीच रात में बिना काम के निकले तीन युवकों को पुलिस ने पकड़ लिया। नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उसे थाने लाया गया था। पुलिस के पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम जय पुराणी बताया। इसी बीच होमगार्ड की पोशाक में एक युवक डी स्टाफ के कार्यालय में घुस गया। उसने अपना नाम चिंतन पुराणी बताते हुए कहा कि जय पुराणी मेरा सगा भाई है। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने बताया कि जय के खिलाफ कर्फ्यू उल्लंघन की कार्रवाई चल रही है। यह सुननते ही होमगार्ड आक्रोसित हो गया और कहने लगा कि देखता हूं कि कौन मेरे भाई के खिलाफ कार्रवाई करता है। इतना ही नहीं आरोपी के पुलिसकर्मी भाई ने पुलिस स्टेशन में जमकर हंगामा किया और पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के कागजात को फाड़ना शुरू कर दिया। कृष्णानगर पुलिस ने होमगार्ड चिंतन के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।

पाटीदार समुदाय ने गुजरात में सीएम पद को लेकर दावेदारी जताई

अहमदाबाद।

गुजरात में फिर पाटीदार समाज ने हुंकार भरी है, समाज की विविध संस्थाओं के पदाधिकारियों ने खोडलधाम पर बैठकर कर गुजरात का अगला सीएम पाटीदार समाज का बनाने का एलान किया है। गुजरात के लेउवा व कड़वा पाटीदार समाज की सात प्रमुख संस्थाओं के पदाधिकारियों ने राजकोट जिले के कागवड धाम पर शनिवार सुबह बैठक की। इसमें खोडल धाम ट्रस्ट, उमिया धाम ट्रस्ट, सिदसर, राजकोट, सूरत की पाटीदार संस्थाओं के पदाधिकारी शामिल हुए। खोडलधाम के प्रमुख ट्रस्टी नरेश पटेल ने बैठक में कहा की गुजरात का अगला मुख्यमंत्री पाटीदार समाज से होना चाहिए। ? गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल पाटीदार समाज से ही आते हैं, लेकिन पाटीदार समाज सरकार में अपनी राजनीतिक उपेक्षा के कारण नाराज नजर आ रहा है। पाटीदार आगामी चुनाव से पहले सीधे मुख्यमंत्री पद को लेकर दावेदारी जताई। इससे आगामी दिनों में गुजरात की राजनीति और गरमा सकती है। आगामी १५ जून को गांधीनगर में भाजपा विधायकों की बैठक होनी है। सरकार व भाजपा के आला नेता इसमें शिरकत करेंगे।

गौरतलब है कि १४ जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी गुजरात आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी लंबे समय से गुजरात में अपनी सियासी जमीन तलाश रही है। कुछ माह पहले हुए महानगर पालिका चुनाव के दौरान सूरत में आम आदमी पार्टी को एक झटके में २८ सीटें मिल गई और प्रमुख विपक्षी दल बन गई। आप आगामी विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आप को सूरत में भी पाटीदार समाज की कांग्रेस से नाराजगी का लाभ हुआ था। अब पाटीदार की भाजपा से नाराजगी का लाभ उठाने के लिए आप हर तरह की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी की गुजरात मीडिया प्रभारी तुली बनर्जी ने बताया कि केजरीवाल १४ जून को गुजरात के गांधीनगर में आएंगे। हालांकि उनकी इस यात्रा के बारे में मीडिया को अभी तक अधिक जानकारी नहीं दी गई।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को प्रवासी मजदूरों के लिए तुरंत सामुदायिक रसोई खोलने का आदेश दिया

अहमदाबाद।

महामारी की दूसरी लहर खत्म होने और लॉकडाउन को कम करने के लिए आ रही है देश भर की सरकारें अर्थव्यवस्थाओं को खोलने के लिए अथक प्रयास कर रही हैं। अब विनिर्माण इकाइयों, उद्योगों और निर्माण स्थलों को फिर से शुरू करने का समय है।

हालांकि, हमारे देश में प्रवासी और प्रवासी श्रमिकों की एक बड़ी समस्या है और इन श्रमिकों को इस भयानक महामारी के दौरान भूख, आश्रय और बेरोजगारी की कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है। तो अब महामारी के बाद बाजार में स्वस्थ मजदूरी मिलना अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी समस्या हो सकती है। इन प्रवासी कामगारों की दुर्दशा को देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 24 मई, 2021 को एक आदेश पारित किया है। जिसमें प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को तत्काल आधार पर कम्युनिटी किचन स्थापित करना है और

इन योजनाओं को राज्यवार प्रचारित करने का भी निर्देश दिया है ताकि जरूरतमंद व्यक्ति ऐसी योजनाओं का लाभ उठाना शुरू कर सकें।

जुलाई, 2017 में, श्री विजय रूपानी के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने राज्यव्यापी “श्रमिक अन्नपूर्णा योजना” की घोषणा की और इसने असंगठित क्षेत्र के निर्माण श्रमिकों को 10 रुपये प्रति निर्माण स्थल पर गर्म पौष्टिक संपूर्ण भोजन उपलब्ध कराने की भी योजना बनाई।

इस योजना से 24000 से अधिक मजदूर भी लाभान्वित हुए सबसे कठिन महामारी के समय में भी जब प्रवासियों को राज्य सरकार द्वारा भोजन की आवश्यकता होती है। कोविड महामारी के कारण पिछले 1 साल से सभी 100 अन्नपूर्णा फूड स्टॉल बंद हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को स्वस्थ कम्युनिटी किचन को जल्द से जल्द फिर से खोलने का निर्देश दिया हैयह महत्वपूर्ण है कि राज्य सरकार सामुदायिक सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए त्वरित और त्वरित कार्रवाई करे सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में जारी एक आदेश के अनुसार, प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को निर्देश दिया गया है। उन्होंने तुरंत सामुदायिक रसोई की स्थापना की, जिसके लिए सही समय आया चला गया और गुजरात सरकार को श्रमिक अन्नपूर्णा योजना को फिर से शुरू करने पर वास्तव में पुनर्विचार करना चाहिए ताकि प्रवासी श्रमिकों का स्वागत नई आशा के साथ काम शुरू करने के लिए किया जा सके।

यह एक महत्वपूर्ण समय है जब माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्र को संबोधित किया है।

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, सम्पादकः संजय रमाशंकर मिश्रा द्वारा ११४, न्यू प्रियंका टाउनशीप अपार्टमेन्ट, डिंडोली, उधना, सुरत (गुजरात) प्रिन्टर्स- भूनेश्वरा प्रिन्टर्स, प्लाट नं. 29, परमानन्द इण्डस्ट्रीयल सोसायटी, चौकसी मील के पास, उधना मगदल्ला रोड़ (गुजरात) से मुद्रित एवं ११४, न्यू प्रियंका टाउनशीप अपार्टमेन्ट, डिंडोली, उधना, सूरत (गुजरात) से प्रकाशित। कार्यालय फोनः 0261-2274271, (न्यायिक क्षेत्र सूरत रहेगा)